सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 134, नई दिल्ली । गुरुवार, 25 जुलाई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने किरदार की हिफाजत जान से बढ़कर कीजिये, क्योंकि इसे जिंदगी के बाद भी याद किया जाता है।

03 आतिशी ने कांवड़ शिविर का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया

06 सुख के सपनों का दुख

08 जिला कलक्टर शेखावत की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित

दिल्ली परिवहन विभाग की कथनी और करनी में अंतर, फिर भी उपराज्यपाल और मुख्य सचिव चुप

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग की घोषणाओं में दिल्ली की जनता को प्रदूषण से मुक्त करवाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यावसायिक सवारी से लाने का लक्ष्य बताया जाता रहता है पर दिल्ली में जनता की सेवा में लगे वाहन मालिकों की मांग के बाद भी दिल्ली में अपने निजी कारणों से इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता होते हुए भी पुराने वाहनों की जगह नए इलेक्ट्रिक वाहन से बदलने की इजाजत नहीं दे रहे और उसके लिए विभाग की शाखा से चलाई गई फाइल को पिछले कई महीनों से आला अधिकारी अलग अलग बात लिख कर वापिस शाखा में भेजते आ रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जांच एजेंसियों से भारत की सड़को पर चलने और पंजीकरण प्राप्त करने के प्रमाण पत्र के साथ दिल्ली परिवहन विभाग से राज्य अप्रूवल प्राप्त वाहनों और वाहन मालिकों द्वारा स्वयं अपने पुराने वाहन को बदल कर नए इलेक्ट्रिक वाहन से बदलने की मांग के बाद भी

इजाजत नहीं देना सिद्ध करता है की दिल्ली में बढ़ते प्रदुषण पर नियंत्रण करने के लिए कही गई बाते सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए है। इसी के साथ जनता को मोहल्ला बस सेवा के नाम पर सुखद सवारी सेवा प्रदान करने का नाम लेकर ख्याति अर्जित करने में लगे हैं जब की यह स्वयं परिवहन विभाग और दिल्ली सरकार भी जानती है की 9 मीटर की बस किसी मोहल्ले में जा ही नहीं सकती। यह सवारी सेवा दिल्ली में चल रही क्लस्टर एवम्-अन्य कंपनियों के द्वारा संचालित बस रूट और मुख्य सड़को पर ही चल सकती है। जब यह वाहन मोहल्ले में जनता को सेवा प्रदान ही नहीं कर सकते तो इसका नाम मोहल्ला बस सेवा क्यों? दिल्ली में मोहल्ला बस सेवा के लिए अगर वाहन की जनता के लिए आवश्यकता है तो वह वाहन कम लंबाई और चौड़ाई के चाहिए जिससे जनता को घर से मुख्य सड़को, मुख्य बाजारों और अपने गंतव्य स्थान से गंतव्य स्थान पर पहुंचने की सुविधा उपलब्ध हो ना की पहले की तरह मुख्य सड़को पर चलने वाली सेवा। **जनता को गुमराह कर अपना स्वार्थ/ हठ करने वाले अधिकारियों पर दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्य सचिव को रोक लगानी चाहिए पर** रोक तो दूर की बात है उनसे इस बाबत सवाल भी नहीं पूछते। आख़िर क्यों?

केंद्र ने नई GNSS-आधारित टोल सिस्टम के डिटेल्स किए पेश, जानें इसके फीचर्स और फायदे

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद के सामने सैटेलाइट-आधारित नेविगेशन सिस्टम की मदद से टोल टैक्स वसूली के लिए किए गए एक पायलट अध्ययन के बारे में जानकारी रखी। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस कॉन्सेप्ट को बंगलूरू-मैसूर खंड राष्ट्रीय राजमार्ग-275 और पानीपत-हिसार खंड राष्ट्रीय राजमार्ग-709 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-71ए) पर पायलट आधार पर लागू किया गया था।

मंत्री ने उच्च सदन को सूचित किया कि केंद्र सरकार ने मौजूदा FASTag (फास्टैग) सुविधा के अलावा नेशनल हाईवे के चुनिंदा सेक्शन पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) सिस्टम को शुरू में पायलट आधार पर लागू करने का फैसला किया है। GNSS, GPS (जीपीएस) और GLONASS (ग्लोनास) जैसी उपग्रह-आधारित नेविगेशन प्रणालियों के लिए एकसाथ में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। गडकरी ने पहले कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का फास्टैग इकोसिस्टम के साथ GNSS-आधारित ETC सिस्टम को इंटीग्रेट करने की योजना है। जिसके शुरुआती चरण में एक हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। जिसमें RFID-आधारित ETC और GNSS-आधारित ETC दोनों एक साथ संचालित होंगे। उन्होंने संसद को यह भी बताया कि परियोजना में GNSS-आधारित ETC का इस्तेमाल करने वाले वाहनों के लिए स्वतंत्र रूप से गुजरने के लिए डेडिकेटेड लेन का प्रस्ताव है। जैसा कि जीएनएसएस-आधारित ईटीसी ज्यादा व्यापक हो जाता है। सभी लेन आखिरकार जीएनएसएस लेन में परिवर्तित हो जाएंगे। समाचार एजेंसी एएनआई ने एक रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है।

GPS-आधारित टोल कलेक्शन के फायदे

GNSS-आधारित टोल कलेक्शन एक बाधा रहित तरीका है। जिससे यात्रियों से उस विशेष हाईवे सेक्शन पर तय की गई दूरी के आधार पर शुल्क लिए जाने की उम्मीद है। भारत में GNSS-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के कार्यान्वयन से नेशनल हाईवे पर वाहनों के सुगम आवागमन की सुविधा होने की उम्मीद है। इसमें हाईवे यूजर्स को कई फायदे देने की योजना बनाई गई है। जिसमें बाधा रहित, फ्री-फो टोलिंग शामिल है, जो दूरी-आधारित होगा।

मिनटों में दिल्ली से मेरठ, नमो भारत आसान करेगी सफर; आया बड़ा अपडेट

दिल्ली-मेरठ के बीच चलने वाली नमो भारत ट्रेन जल्द शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल गाजियाबाद में ट्रेन चल रही है। कुछ माह बाद यह दिल्ली-मेरठ के पूरे कॉरिडोर पर दौड़ती नजर आएगी। ट्रैक बिछाने एवं ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन (ओएचई) इंस्टॉलेशन का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रोजेक्ट का काम 98 प्रतिशत तक हो चुका है।

नई दिल्ली। दिल्ली-मेरठ की दूरी अगले कुछ ही माह में सिमटने वाली है। 82 किमी लंबा आरआरटीएस कॉरिडोर (RRTS Corridor) 80 किमी यानी करीब 98 प्रतिशत तक बन गया है। केवल दो किमी का वायाडक्ट निर्माणाधीन है। कॉरिडोर पर ट्रैक बिछाने का कार्य भी साथ-साथ चल रहा है। एक बार ट्रेन शुरू हो जाने पर दिल्ली से मेरठ की दूरी 60 मिनट से भी कम समय में पूरी हो जाएगी।

34 किमी में फिलहाल चल रही नमो भारत

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर 25 स्टेशन होंगे। गाजियाबाद में साहिबाबाद से मोदीनगर नॉर्थ तक आठ स्टेशनों, साहिबाबाद, गाजियाबाद, डीपीएस राजनगर गुलधर, दुहाई, दुहाई डिपो, मुराद नगर, मोदी नगर साउथ और मोदी नगर नार्थ पर 34 किमी के सेक्शन में नमो भारत ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। जल्द ही मेरठ साउथ स्टेशन भी जुड़ने वाला है। इस स्टेशन के जुड़ने से आरआरटीएस संचालित खंड की लंबाई 42 किमी हो जाएगी।

दिल्ली में 14 किमी कॉरिडोर

दिल्ली में आरआरटीएस कॉरिडोर की लंबाई 14 किमी है, जिसमें नौ किमी का एलिवेटेड जबकि पांच किमी का भूमिगत स्ट्रेच है। दिल्ली सेक्शन में सराय काले खां, न्यू अशोक नगर और आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन शामिल हैं, जिनका निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

साल के अंत में ट्रायल हो जाएगा शुरू

अधिकारियों का कहना है कि अनुमान है कि इस साल के अंत तक कॉरिडोर के दिल्ली हिस्से पर ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। दिल्ली के एलिवेटेड हिस्से के लिए वायाडक्ट निर्माण सराय काले खां स्टेशन तक पूर्ण हो चुका है। अब ट्रैक बिछाने और ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन (ओएचई) इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है।

मेरठ में इतने हैं स्टेशन, 23 किमी का सेक्शन

वहीं, मेरठ में 23 किमी के सेक्शन में चार आरआरटीएस और नौ मेट्रो स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। मेरठ में सात किमी का हिस्सा भूमिगत है, जिसमें मेरठ सेंट्रल, भैंसाली और बेगमपुल स्टेशन हैं। सभी का निर्माण कार्य एडवांस स्टेज में है। मेरठ में मेरठ साउथ (आरआरटीएस), परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, एमईएस कॉलोनी, दौरली, मेरठ नार्थ और मोदीपुरम स्टेशन एलिवेटेड होंगे तथा मोदीपुरम डिपो स्टेशन ग्राउंड लेवल पर होगा।

मेरठ में वायाडक्ट निर्माण अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही ट्रैक बिछाने की गतिविधियां भी तेजी से जारी हैं। इसके साथ ही ओएचई इंस्टालेशन का कार्य भी आगे बढ़ रहा है। हालांकि दिल्ली से मेरठ तक नमो भारत ट्रेनों का संचालन शुरू करने का लक्ष्य जून 2025 तक है। लेकिन इससे पहले ही हरी झंडी दिखा दी जाएगी।

ऑटो यूनियन का प्रतिनिधि मंडल परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से मिला, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली के ऑटो यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली सचिवालय में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान, प्रतिनिधि मंडल ने परिवहन मंत्री के समक्ष अपने कुछ मुद्दे रखे, जिस पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि दिल्ली सरकार हमेशा ऑटो चालकों का साथ देती रही है और हम आगे भी सरकार से सहयोग मिलने की उम्मीद करते हैं। परिवहन मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को उनके सभी मुद्दों का यथा शीघ्र समाधान कराने का आश्वासन दिया। परिवहन मंत्री ने कहा कि केजरीवाल सरकार शुरू से ही ऑटो चालकों के साथ खड़ी रही है और उनके हितों को प्राथमिकता देती आई है। पिछले 9 सालों में सरकार ने ऑटो चालकों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए उनको कई राहतें देने का काम किया है। सरकार आगे भी ऑटो चालकों के साथ खड़ी रहेगी और उनके हितों को प्राथमिकता देती रहेगी।

दरअसल, दिल्ली के ऑटो यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल ने सचिवालय में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से मुलाकात कर अपने कुछ मुद्दे परिवहन मंत्री के समक्ष रखे। प्रतिनिधि मंडल कहा कि परिवहन विभाग ने बुराड़ी से हटाकर राजपुरा रोड पर कार्यालय बनाया है। लेकिन अभी वहां वाटर कूलर नहीं लगा है और वेटिंग एरिया भी नहीं बना है। इस पर परिवहन मंत्री ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही वहां पर वाटर कूलर लगा दिया जाएगा और शेड लगाकर वेटिंग एरिया बना दिया जाएगा। प्रतिनिधियों ने बताया कि पहले उन्हें ऑटो का लाइसेंस बनवाने लिए ऑटो चलाकर टेस्ट देना पड़ता था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने नया नियम बना दिया है कि अगर ऑटो चलाने के लिए लाइसेंस बनवाना है तो उनको कार चलाकर टेस्ट देना होगा। इससे उन ऑटो चालकों दिक्कत हो रही है, जिनको कार चलानी नहीं आती है और वो ऑटो का लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे हैं। इस पर परिवहन मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर अधिकारियों से बात कर इसके समाधान का रास्ता तलाशेंगे।

इस दौरान ऑटो यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए बहुत सारे काम किए हैं और उन्हें सम्मान दिलाया है। खासकर कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन लग गया था, तब एक साथ सभी ऑटो चालक बेरोजगार हो गए थे। उस दौरान

आमदनी नहीं होने के कारण घर की आर्थिक हालत खराब हो गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनकी इस समस्या को समझा और दो बार 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद की। कोराना के दौरान केवल दिल्ली ही इकलौता राज्य रहा, जहां सरकार ने ऑटो चालकों को आर्थिक मदद की। इसके अलावा उन्हें डिम्टस, सिम, फिटनस समेत कई तरह की फीस देनी पड़ती थी, जिसे सरकार ने माफ कर दिया।

केजरीवाल सरकार से ऑटो चालकों को मिली ये राहतें

- कोरोना में 2 बार 5-5 हजार यानि कुल 10 हजार रूपए दिए।
- डिम्टस की फीस 1420 रुपए सलाना से घटाकर शून्य कर दी।
- सिम की फिस 584 रुपए सलाना से घटाकर फ्री कर दी।
- फिटनस की फिस 600 रूपए सलाना से घटाकर मुफ्त कर दी।
- ऑटो मीटर की रोड ट्राई भी खत्म की।
- ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस पर लगने वाली क्लास बंद कर दी।
- परमिट फीस को 1000 से घटाकर 500 कर दिया।
- आरसी का पता बदलवाले पर हर महीना 500 रुपए (6 हजार सालाना) पेनल्टी लगती थी। इसे घटाकर 100 (1200 रुपए सालाना) कर दिया।
- दिल्ली के अंदर 511 ऑटो स्टैंड बनवाए।

इसके अलावा ये भी काम किए

- ऑटो चालकों के परिवार का भविष्य भी सुरक्षित किया।
- सीएम केजरीवाल ने स्कूलों का कायाकल्प कर दिया
- सभी ऑटो वालों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बुराड़ी के रमेश आटो वाले की बेटी केजरीवाल के सरकारी स्कूल में पढ़कर केंद्रीय विद्यालय में टीचर बन गई।
- 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है और 24 घण्टे बिजली मिलती है।
- मोहल्ला क्लिनिक व अस्पतालों में इलाज फ्री होता है, दवाइयां फ्री मिलती हैं, पानी फ्री मिलता है।

पर्यावरण पाठशाला: फरीदाबाद और गुड़गांव की कहानी, कचरे की जुबानी

अंकुर शरण

फरीदाबाद और गुड़गांव, ये दो शहर जो देश के विकास का प्रतीक हैं,एक तरफ स्मार्ट सिटी और मिलेनियम सिटी का दर्जा प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर, कचरे की समस्या ने इन शहरों के वर्चस्व को धूमिल कर दिया है।

ये बेहद शर्म की बात है कि संसद में इन शहरों को कचरे का सही उपयोग न करने और इसे यहाँ-वहाँ फेंकने के लिए जाना जा रहा है।

फरीदाबाद और गुड़गांव के निवासी इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बधवाड़ी जैसे कचरे के पहाड़ अब इतने बड़े हो गए हैं कि इन्होंने अरावली पर्वतों को भी छोटा कर दिया है। यह स्थिति न केवल पर्यावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है।

अगर आज इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया और उचित कदम नहीं उठाए गए,तो एक दिन ये समस्या महामारी का रूप ले सकती है।यह एक नई महामारी होगी, जो कोरोना से भी बड़ी साबित हो सकती है, जहां दिल्ली और इसके सटे इन महानगरों में जल और वायु दूषित हो जाएंगे। लोगों की मानसिकता दूषित हो जाएगी, क्योंकि जब चारों ओर गंदगी और कचरा होगा, तो स्वच्छ पर्यावरण का सपना अधूरा ही रह जाएगा। फरीदाबाद और गुड़गांव के लोग इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं?

क्या कचरे के ढेर को बस देखते रहना ही हमारी

नियति है?

क्या हमें यह सोचना नहीं चाहिए कि हमारे भविष्य की पीढ़ी किस तरह के पर्यावरण में पलेगी?

जरूरत है कि हम सभी मिलकर इस समस्या का हल निकालें।

कचरे का उचित निस्तारण, रीसाइक्लिंग, और सड़कों पर सफाई जैसे उपायों को प्राथमिकता दें।

यह केवल प्रशासन का काम नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने आस-पास के क्षेत्र को स्वच्छ रखें। एक स्वस्थ पर्यावरण में ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, और तभी हम अपने शहरों के स्मार्ट और मिलेनियम सिटी होने का गौरव महसूस कर सकते हैं।

आइए, मिलकर कचरे को सही जगह पर फेंकें, रीसाइक्लिंग की आदत डालें, और एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर बढ़ें।

ताकि फरीदाबाद और गुड़गांव एक बार फिर अपने वर्चस्व को पा सकें,

और हम सभी को एक स्वस्थ और सुंदर पर्यावरण मिल सके।

indiangreenbuddy@gmail.com

चिलचिलाती गर्मी में MP के इन पांच हिल स्टेशनों को करें एक्सप्लोर, खूबसूरती देख आ जाएगी मजा

चिलचिलाती गमी में हर कोई किसी ठंडी जगह पर जाना चाहता है। अगर आप भी गर्मियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपको मध्य प्रदेश के टॉप 5 हिल स्टेशनों के बारे में बताने जा रहे हैं।

इस चिलचिलाती गमी में हर कोई किसी ठंडी जगह पर जाना चाहता है। इन दिनों लोग हिल स्टेशन जाते हैं। हिल स्टेशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले उत्तराखंड, मसूरी और हिमाचल का नाम आता है। लेकिन हर बार इन्हीं जगहों पर जाने से बोरियत होने लगती है। ऐसे में अगर आप भी इन हिल स्टेशनों पर नहीं जाना चाहते हैं, तो आप मध्य प्रदेश के हिल स्टेशनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश अपने ऐतिहासिक चमत्कारों और वाइल्ड सेंचुरी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन यहां पर खूबसूरत हिल स्टेशन भी हैं। हरियाली के बीच मौजूद ये हिल स्टेशन न सिर्फ गर्मियों से राहत देते हैं, बल्कि यह आपको रोमांचित करने का काम भी करते हैं। ऐसे में अगर आप भी गर्मियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको मध्य प्रदेश के 5 हिल स्टेशनों के बारे में बताने जा रहे हैं।

पंचमढ़ी

मध्य प्रदेश के सबसे खूबसूरत और फेमस हिल स्टेशनों की लिस्ट में शामिल पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। सतपुड़ा रेंज के भीतर बसा यह शहर हरे-भरे जंगलों, झरने और प्राचीन गुफाओं से भरा है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो आप यहां पर ट्रेकिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। यहां पर ऊंचाई से काफी शानदार नजारा देखने को मिलता है। बता दें कि यहां पर जटाशंकर और बी-फॉल्स को एक्सप्लोर करना न भूलें। हरे-भरे जंगलों में ऊंचाई से गिरते पानी की आवाज भी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।

तामिया

प्रकृति की गोद में बसा तामिया एमपी का छिपा हुआ रत्न है। यह जगह उन लोगों के लिए जन्नत से कम नहीं है, जो एडवेंचर और नेचर से प्यार करते हैं। तामिया 1,100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह हिल स्टेशन शहरी जीवन से दूर शांति और सुकून देता है। यहां पर चट्टानों के किनारे ब्रिटिश काल के जमाने के घर बने हैं। यहां पर आप सतपुड़ा रेंज के घने जंगलों के बीच ट्रेकिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ ही यहां पर तामिया वॉटरफॉल जरूर देखें।

चंदेरी

मध्य प्रदेश का चंदेरी शहर अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। 656 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर बसा चंदेरी विरासत और प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा मिश्रण है। इसके अलावा यह शहर चंदेरी के सूट और साड़ियों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। चंदेरी में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और वरुण धवन की फिल्म सुई धागा की शूटिंग हुई थी। आप यहां पर चंदेरी का किला एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर महलों से घिरी घुमावदार गलियों और प्राचीन स्मारकों को देख सकते हैं।

मांडू

मध्यप्रदेश की ऑफबीट डेस्टिनेशन में शामिल मांडू में हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। मांडू विंध्य पर्वत श्रृंखला पर बसा है और यह छठी शताब्दी के वास्तुशिल्प से सजा है। मांडू का किला बीते युग की कहानियां बयां करता है। वहीं समुद्र के बीच राजसी जहाज महल तैरता हुआ लगता है और रूपमती का मंडप नर्मदा घाटी का बेहद शानदार दृश्य पेश करता है। आपको यहां पर सनसेट का नजारा मिस नहीं करना चाहिए।

अमरकंटक

मैकाल पहाड़ियों की हरी-भरी हरियाली के बीच अमरकंटक हिल स्टेशन भी काफी शानदार है। इसे एमपी का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है। माना जाता है कि यह पवित्र नदियों नर्मदा, सोन और जोहिला का सोर्स है। इसके कारण इस जगह का आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा आप यहां पर प्राचीन कपिलधारा झरना और नर्मदा मंदिर देख सकते हैं। अगर आप सेल्फ डिस्कवरी के शौकीन हैं, तो आपको यह जगह निराश नहीं करेगी।

हनीमून फेज के बाद रिश्ते की बुझी आग को फिर से कैसे जगाएं?

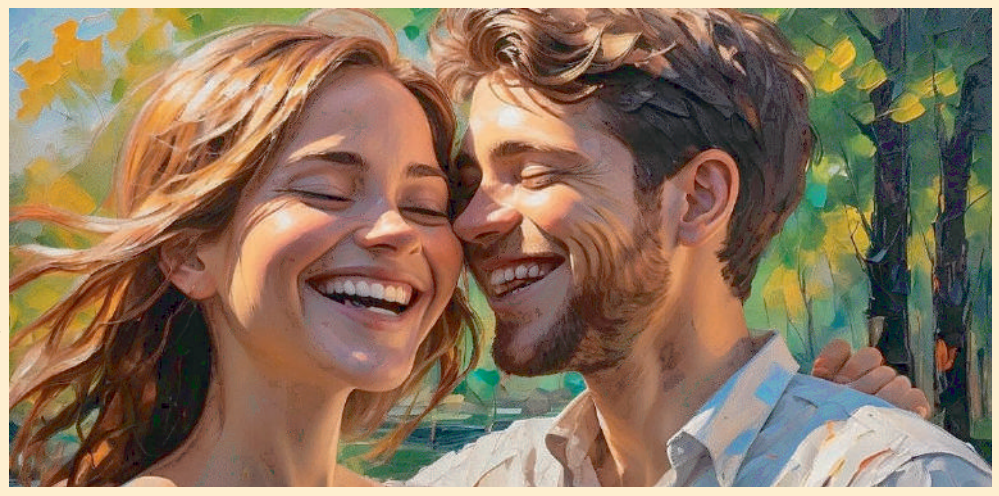

हनीमून चरण के बाद, यह बहुत आम है कि लोग सेक्स करने की इच्छा खोना शुरू कर देते हैं, खासकर अपने पार्टनर के साथ। तो, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? हम अपने रिश्ते में हनीमून चरण की चिंगारी को कैसे बनाए रख सकते हैं?

हम सभी जानते हैं कि रिश्ते विभिन्न चरणों से गुजरते हैं और ये चरण किसी न किसी तरह से हमारे यौन जीवन को प्रभावित करते हैं। हनीमून चरण के बाद, यह बहुत आम है कि लोग सेक्स करने की इच्छा खोना शुरू कर देते हैं, खासकर अपने पार्टनर के साथ। तो, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? हम अपने रिश्ते में हनीमून चरण की चिंगारी को कैसे बनाए रख सकते हैं?

ये बहुत ही आम सवाल हैं, जो हर किसी के दिमाग में आते हैं। देखा जाए तो इन सवालों से खुद को घिरे हुए पाना जरुरी है क्योंकि ये अंतरंगता और संबंध बनाए रखने के बारे में एक स्वाभाविक चिंता को दर्शाते हैं। हालाँकि, एक्सपर्ट्स के अनुसार, पूछने के लिए ये सही प्रश्न नहीं हो सकते हैं। इसके बजाय, ऐसे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो यौन ज़रूरतों और इच्छाओं के बारे में, जिनपर लोगों को अपने पार्टनर के साथ चर्चा करने की जरुरत है।

सबसे पहले, यह पता लगाना आवश्यक है कि आप और आपके पार्टनर के लिए अंतरंगता का क्या अर्थ है। अंतरंगता केवल शारीरिक संबंध के बारे में नहीं है, इसमें भावनात्मक निकटता और आपसी समझ भी शामिल है।

रिलेशनशिप थेरेपिस्ट ल्यूसिल शेकलटन ने लिखा, 'इस पोस्ट में, मैं आपको अपने साथी के साथ अपने सेक्सुअल कनेक्शन और एक यौन प्राणी के रूप में खुद के साथ अपने रिश्ते का पता लगाने के लिए कुछ बातें बताने जा रहा हूँ और साथ ही आपको साथ मिलकर कुछ सवाल पूछने के लिए कहूँगा। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यह आपको एक-दूसरे से बात करने के लिए प्रोत्साहित करेगा कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं क्योंकि इच्छाओं में अंतर को प्रबंधित करने के लिए संचार महत्वपूर्ण है।'

अपने साथी के साथ अपने यौन संबंध के बारे में खुद से क्या सवाल पूछें?

आपके जीवन के इस मोड़ पर आपके लिए यौन संबंध का क्या मतलब है? क्या आपके लिए अपने रिश्ते में यौन अंतरंगता रखना महत्वपूर्ण है? क्या आप अपने साथी के सामने अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में सहज महसूस करते हैं? पहल कौन करता है? क्या पहल इस तरह से की जाती है कि यौन संबंध आकर्षक हो? जब यौन संबंध होता है, तो क्या यह आनंददायक होता है? जब आप सोचते हैं कि आप वास्तव में किस तरह का यौन संबंध चाहते हैं, तो यह आपके वर्तमान यौन संबंध से किस तरह अलग होगा? अपने साथी के साथ यौन संबंध से आपको क्या मिलता है जो आपको अकेले यौन संबंध से नहीं मिलता?

अपने साथ अपने रिश्ते के बारे में खुद से ये सवाल करें

आप अपने शरीर में कितना सहज महसूस करते हैं? क्या आप अपने शरीर के बारे में जो महसूस करते हैं, उसका असर आपकी यौन इच्छा पर पड़ता है? आपके शरीर में उत्तेजना होने पर कैसा महसूस होता है? वह भावना किस वजह से होती है? क्या आपको लगता है कि आप बिना किसी निर्णय के अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकते हैं? क्या आप अपने साथी के प्रति प्रतिक्रिया में इच्छा महसूस करते हैं? या यह अपने आप होता है? आपके ब्रेक (टर्न-ऑफ) और एक्सीलेटर (टर्न-ऑन) क्या हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी क्षमता (आपका मानसिक और भावनात्मक तनाव) आपको यौन रूप से कैसे प्रभावित करती है?

रेस्टोरेंट स्टाइल में घर पर बनाएं साउथ इंडियन सांभर, नोट करें रेसिपी

साउथ इंडिया सबसे फेमस डिश है डोसा और इसके साथ ही सांभर जो परोसा जाता है, वो बहुत ही टेस्टी होता है। ज्यादातर लोगों को सांभर खाना बहुत पसंद करते हैं। आमतौर पर हर घरों में सांभर बनाया जाता है आइए जानते हैं इसकी रेसिपी।

साउथ इंडिया में डोसा सबसे ज्यादा खाया जाता है इसके साथ ही सांभर परोसा जाता है। सांभर एक प्रमुख डिश है। दाल की जगह लोग सांभर को खाना पसंद करता है। हेल्थ की दृष्टि से यह डिश काफी फायदेमंद है। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी।

सांभर की सामग्री

- अरहर की दाल- 1 कप - सांभर मसाला- 2 चम्मच
- हल्दी - आधी चम्मच - नमक - स्वादानुसार
- सरसों- 1 चम्मच - करी पत्ता - 6-8
- इमली का पानी - 1 कप - साबुत लाल मिर्च - 2
- गाजर - 1 कप कटी हुई - प्याज - 1 कटा हुआ
- बैंगन - 1 कटा हुआ - सहजन की फली - 6-7 स्टिक
- हरा धनिया- 2 चम्मच कटा हुआ - तेल - 2 चम्मच

सांभर बनाने का तरीका

- सबसे पहले अरहर की दाल को पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद एक पैन में एक चम्मच तेल गर्म करें और प्याज सहित सभी सब्जियां डालकर भूनें।
- सब्जियां भूनने के बाद उसमें नमक और हल्दी मिलाएं। जब सब्जियां पक जाए, तो फ्लेम बंद कर दें।
- इसके बाद कुकर में दाल डालें और 2-3 सीटी आने तक पका लें। जब दाल पक जाए, तो इसमें पकी हुई सभी सब्जियां डालकर मिलाएं और ढक्कन खोलकर उबालें।
- अब उबलती हुई दाल में सांभर मसाला डालकर मिलाएं साथ ही तड़का लगाने वाला पैन गर्म करें।
- फिर पैन में तेल डालें। तेल गर्म होने के बाद उसमें साबुत लाल मिर्च, सरसों और करी पत्ता डालकर भूनें।
- अब इस तड़के को दाल में डालकर मिक्स करें। ऊपर से हरा धनिया डालकर गार्निश करें और सांभर बनकर तैयार है। इसे आप चवाल, इडली, डोसा आदि के साथ सर्व कर सकते हैं।

पसीने की बदबू को दूर करने के लिए करते हैं डियोड्रेंट का इस्तेमाल, तो पहले जान लें ये नुकसान

हम सभी रोजाना कई सारे केमिकल्स के बीच जीते हैं। लेकिन यह हमारी लाइफस्टाइल का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। कुछ को तो हमने शौक या लग्जरी के कारण अपना लिया है। इनमें से एक हिस्सा कॉस्मेटिक का है। साबुन से लेकर शैंपू और परफ्यूम से लेकर लोशन और डियो स्टिक तक हर चीज में रसायन होता है। जाहिर है जब हमारा शरीर कई रसायनों से होकर गुजरेगा, तो वह रासायनिक प्रतिक्रिया भी देगा। डियोड्रेंट भी इसे के अंतर्गत आता है। भीषण गर्मी हो या बारिश के उमस भरे दिन लेकिन शरीर पर खुशबूदार डियो लगाने भर से मन अच्छा हो जाता है। त्वचा की एसिडिटी को बढ़ाकर डियोड्रेंट बदबू पर कंट्रोल करता है। लेकिन यह पसीने को कंट्रोल नहीं करना है। डियोड्रेंट एक तरह का कॉस्मेटिक है, जो रसायनों से बनाए जाते हैं। पसीने की बदबू को रोकने के लिए इनमें परफ्यूम का उपयोग होता है। वहीं इसमें एल्कोहल भी होता है। यही वजह है कि जब आप डियोड्रेंट त्वचा पर अप्लाई करते हैं, तो आपकी त्वचा रूखी और रंगहीन हो सकती है।

एलर्जी और डियो

बता दें कि डियो की वजह से कई बार एलर्जी ट्रिगर हो जाती है। जिसके कारण स्किन पर दाने, लाली, रैशेज, खुजली, जलन होना या त्वचा पर पपड़ी बनना या सूजन आने के अलावा सांस संबंधी लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। आमतौर पर यह कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का एक प्रकार होता है। क्योंकि डियो में अल्कोहल, कृत्रिम सुगंध, एल्युमिनियम, पैराबीन्स जैसे प्रिजर्वेटिव्ज, रंग या अन्य रसायन होते हैं। जिनकी वजह से ऐसी समस्या हो सकती है।

इन बातों का रखें खास ख्याल

अगर आपकी स्किन संवेदनशील है, तो आपको डियो का चुनाव बहुत सतर्कता के साथ करना चाहिए। अच्छा होगा यदि आप विशेषज्ञ की परामर्श से लें।

आपको इस बात तो याद रखना चाहिए कि पसीना बदबूदार नहीं होता है, बल्कि त्वचा पर पलने वाले बैक्टीरिया के कारण बदबू बनती है। इसलिए अगर आप बॉडी ओडर से परेशान हैं, तो पहले इसकी वजह जानें। न कि बिना सोचे-समझे ढेर सारे डियो का इस्तेमाल करने लगें। क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई ऐसी परेशानी हो, जिसका इलाज जरूरी हो।

आर्थराइटिस की समस्या को गंभीर कर सकता है मोटापा, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

आर्थराइटिस भी एक ऐसी ही समस्या है, जो मोटापे का परिणाम हो सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोटापा किस तरह से गठिया को प्रभावित करता है और इनमें क्या संबंध है।

आजकल की बदलती लाइफस्टाइल के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं। इन्हीं समस्याओं में से एक मोटापा है। जो लोगों को तेजी से अपना शिकार बना रही है। खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान के कारण लोगों का तेजी से वजन बढ़ रहा है। मोटापा एक गंभीर समस्या है, जो दुनियाभर में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर रहा है। WHO ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी की है। मोटापा कई सेहत संबंधी समस्याओं की वजह बन सकता है।

बता दें कि आर्थराइटिस भी एक ऐसी ही समस्या है, जो मोटापे का परिणाम हो सकता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोटापा किस तरह से गठिया को प्रभावित करता है और इनमें क्या संबंध है।

जानिए मोटापा और गठिया में संबंध

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, जोड़ों में सूजन, परेशानी और मूवमेंट में कमी होना गठिया के लक्षण हैं। यह एक पुरानी बीमारी है। इस बीमारी में जोडों में सूजन और कठोरता आ जाती है। इसको अर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है। मोटापा उन कारकों में से एक है, जो व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार बनाता है। OA गठिया का सबसे प्रचलित प्रकार है। वहीं जब व्यक्ति का वजन बढ़ता है, तो घुटने और कूल्हे सहित वजन सहने वाले जोड़ों पर मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ जाता है।

गठिया को बदतर बना सकता है मोटापा

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें, तो बायोमैकेनिक्स और जोड़ों की अलाइनमेंट को मोटापा बदल सकता है। जिसके कारण असामान्य लोडिंग पैटर्न हो सकता है। जोड़ों को सहारा देने वाले लिगामेंट्स और टेंडन के कमजोर होने की वजह से मोटापा जोड़ों की स्थिरता को अधिक खतरे में डालने का काम करता है। इस कारण जोड़ों की डिजनरेटिव प्रोसेस तेज हो जाती है और उनके डैमेज होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है।

गठिया में जरूरी है वेट लॉस

वजन कम करने से जोड़ों पर शरीर का दबाव कम हो सकता है। साथ ही इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा और इंटेंसिटी कम हो सकती है। गंभीर गठिया होने पर जब इलाज, लाइफस्टाइल में बदलाव से भी मरीजों को लंबे समय तक राहत नहीं देते हैं। तो फिर घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी जरूरी हो सकती है। पिछले कुछ सालों में रोबोटिक आर्म-असिस्टेड तकनीक ने दुनियाभर में ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को बदल दिया है।

रोबोटिक्स तकनीक

इस तकनीक के बारे में बताते हुए डॉक्टर ने कहा कि मरीज के रोगग्रस्त जोड़ का रोबोटिक्स तकनीक सीटी स्कैन के आधार पर एक वर्चुअल 3डी मॉडल बनाने में सहायता करती है। बता दें कि यह तकनीक डॉक्टर्स को ऑपरेशन से पहले सर्जरी की योजना बनाने, रिप्लेसमेंट अलाइनमेंट तय करने और सटीक हड्डी काटने में सहायक होती है।रू कर देती थी. जैसे ही वह सब ठीक हुआ, मुझे मेरे बेबी की सेफ्टी और उससे जुड़े कई खतरनाक डर लगने लगे. मैं इस दौरान बहुत ज्यादा सेंसटिवि हो गई थी.' वो आगे बताती हैं, 'इस सब के दौरान जसिने मुझे सपोर्ट कयिा वो थे परिवार और मेरे दोस्त. मेरी मां ने मेरा बहुत साथ दयिा और वो हमेशा सलाह देती थीं. फहद और मेरी मां मेरे हर डॉक्टर अपोइंटमेंट में मेरे साथ थे. ये दोनों लेबर रूम में भी मेरे साथ थे और पछिले 8 महीनों से वह मेरे साथ ही हैं और उनसे ही मैंने अपनी बेटी की मां बनना सीखा है''

स्वरा भास्कर थेरेपी सेशन लेने पर जरूरत पर जोर डालते हुए कहती हैं, 'मैं साल 2020 से थेरेपी पर हूं और मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कतिनी जरूरी है. चाहे ब्रेकअप हो या फिर हार्टब्रेक इसने मुझे हमेशा संभाला. मेरे पोस्टपार्टम डप्रिेशन के दौरान भी थेरेपी ने मेरी बहुत मदद की.' एक्ट्रेस आगे कहती हैं कि पोस्टपार्टम डप्रिेशन कोई कतिाबी बात नहीं ये एक सच है और आप जनिपर भरोसा करते हैं, उनसे आप इसके बारे में बात कर सकते हैं.

रेलवे को मिला भारी बजट ,पर यात्री छूट में रहा कट

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। भारतीय रेल के बजट में इस साल रिकार्ड पैसा मिला है ।मगर यात्रियों की और से सिरे से मुंह फेर लिखाया है। यात्रियों के भाडे ,समेत सिनीयर सिटीजन को भी कोई छूट नहीं दी गई है ।इस बार रेलवे को बम्पर बजट के तहत 2,62,200 करोड रूपये आवंटित किये गए हैं । जिसमें से 1 लाख करोड रूपये से ज्यादा सेफ्टी पर फोकस खर्च करने का इरादा है। इसमें सुरक्षा कवच लगाना शामिल है। ताकि आए दिन की ट्रेन भिडंत की दुर्घटनाओ से निजात मिल सके। इसके अलावा वंदे भारत ,वंदे मैट्रो,अमृत भारत, भ,समेत अन्य नए तरह के कोच बनाने पर लगातार काम किया जा सके ।रेल मंत्री अश्विन वैष्णव के मुताबिक अधिक ट्रेन बनाने पर जोर दिया जा रहा है ।.वहीं 2500 अतिरिक्त जनरल डिब्बे बनाने की तरफ खासा प्रयास है। दरअसल इस वक्त देशभर में करीब 700 करोड से ज्यादा लोगों ने सफर किया है ।इसलिए आने वाले समय में 10 हजार जनरल कोच तक बढान जाने का लक्ष्य है। रेलवे आगे की योजना के तहत पुराने ट्रेकको बदलने ,नये ट्रेक को बिछाने के अलावा सिग्नलिंग सिस्टम में बेहतर सुधार लाने के अलावा डबल लाइनों को बढाने.के साथ-साथ नई तकनीक लाने पर काम किया जाएगा। इनमें नये फ्लाईओवर, अंडर पास भी शामिल है। यात्रियों को खासकर बुजुर्गो के लिए पहले की तरह रेल भाडे में कोई छूट नहीं दी गई है। कोरोना में छीनी गई इस छूट को लेकर कई संगठनों,यूनियनों,सिनियर सिटीजनों की संस्थाओं ने पीएम, समेत रेल मंत्री से चिरौरियां कर चुके है। पर बुजुर्गों के लिए सरकार का दिल नहीं पसीजा है। उल्लेखनीय है कि रेलवे को आम बजट में पहली बार 2021 में 1 लाख करोड रूपये से अधिक आवंटित किए गए थे। वहीं 2022 में 1.40 हजार करोड रूपये आवंटित हुए। 2023 में 2 लाख 40 हजार करोड रूपये मिला ।जबकि फरवरी के अंतरिम बजट में रेलवे को 2.55 लाख करोड रूपयेसे ज्यादा आवंटित किए गए थे। और अब साल 2024 के बजट में 2.62 लाख करोड रूपये आवंटित किए गए है।

राजस्व मंत्री आतिशी ने कश्मीरी गेट स्थित कांवड़ शिविर का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया

सुषमा रानी

नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार कांवड़ियों की सुविधा के लिए दिल्लीभर में 185 कांवड़ शिविर लगा रही है। इससे संबंधित तैयारियों का जायजा लेने के लिए राजस्व मंत्री आतिशी ने बुधवार को कश्मीरी गेट स्थित महाराजा अग्रसेन पार्क के कांवड़ शिविर का निरीक्षण किया।

बता दे कि केजरीवाल सरकार का ये शिविर देश के सबसे बड़े कांवड़ शिविरों में से एक है जहाँ एक समय में लगभग 20,000 कांवड़ियों के रुकने का इंतजाम किया जा सकता है। यहाँ महिला-पुरुष कांवड़ियों के विश्राम के लिए अलग-अलग हॉल व कांवड़ियों के प्रसाद ग्रहण करने के लिए एक बड़ा डाइनिंग हॉल भी तैयार किया गया है।

इस दौरान अधिकारीयों को निर्देश देते हुए राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा कि, कांवड़ शिविर में कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए सभी जरुरी सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम किया जाए ताकि शिवभक्तों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि, सावन के पवित्र महीने में शिवभक्तों की सेवा करना पुण्य और आस्था का काम है। इस दिशा में कांवड़ियों को तमाम सुविधाएँ मुहैया कर केजरीवाल सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है।

उन्होंने कहा कि, पिछले 9 सालों से सावन के पवित्र महीने में केजरीवाल सरकार कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए शिविर लगाती है। इस साल भी दिल्ली भर में 185 कांवड़ शिविर लगाए जा रहे है जहाँ कांवड़ियों के लिए तमाम सुविधाएँ मौजूद रहेंगी। इसमें वाटरप्रूफ टेंट, रहने-सोने की व्यवस्था, साफ़ पानी, शौचालय सहित अन्य व्यवस्था की जाती है। कांवड़ियों के कांवड़ रखने के लिए विशेष स्टैंड मुहैया करवाए जाते है। साथ ही हर कांवड़ शिविर में मेडिकल सुविधाएँ होती है।

उन्होंने कहा कि, इस साल भी सभी शिविरों में 24*7 मेडिकल स्टाफ मौजूद रहेंगे ताकि लंबी दूरी तय कर आ रहे कांवड़ियों का जरुरत पड़ने पर तुरंत उपचार दिया जा सकें और कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए स्थानीय डिस्पेंसरियों को शिविरों से जोड़ा गया है। किसी भी आपात स्थिति के लिए कैट्स एंबुलेंस को जोड़ा गया है। अस्पतालों को कांवड़िये के इलाज के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि हम सभी को कांवड़ियों का धन्यवाद करना चाहिए कि, हरिद्वार से जल लाकर भगवान-भोलेनाथ की भक्ति का जो काम हम नहीं कर पाते वो पुण्य का काम हम सभी के लिए कांवड़िए कर रहे है। ऐसे में इन कांवड़ियों की सेवा करना केजरीवाल सरकार की प्राथमिकता और जिम्मेदारी है और हम अपने कांवड़ शिविरों में शिवभक्त कांवड़ियों के लिए सभी सुविधाएँ सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने अधिकारीयों को निर्देश देते हुए कहा कि, कांवड़ यात्रा के दौरान जिला प्रशासन अलर्ट पर रहे ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े साथ ही शिविर में कांवड़ियों को हर जरुरी सुविधाएँ मिले। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए हर जरुरी कदम सुनिश्चित किया जाए।

बता दे कि सावन महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार से जल लेने जाते है। ऐसे में दिल्ली सरकार राजधानी में जगह-जगह कांवड़ शिविर लगाती है। जहाँ कांवड़ियों के रुकने और आराम करने के लिए हर जरुरी सुविधाएँ मुहैया करवाई जाती है। ऐसे में इस साल भी केजरीवाल सरकार, दिल्ली में कांवड़ियों की सुविधा के लिए लगभग 185 कांवड़ शिविर लगवा रही है और अगले कुछ दिनों में सभी कांवड़ शिविर पूरी तरह तैयार रहेंगे।

बारिश से डूबा जखीरा अंडरपास, पानी के बीचों-बीच फंसा ट्रक; जान बचाने के लिए मशीन पर चढ़े लोग

बुधवार सुबह हुई बारिश के कारण उत्तरी दिल्ली स्थित जखीरा अंडरपास में जलभराव हो गया। इस वजह से आधा अंडरपास पानी में डूब गया। पानी में गुजरते हुए सुबह के समय एक ट्रक बीच में ही फंस गया जिसमें पांच लोग सवार थे। यह लोग अपनी जान बचाने के लिए पास में खड़ी एक मशीन पर चढ़ गए।

दिल्ली। जखीरा अंडरपास में जलभराव होने से लोक निर्माण विभाग के कार्यों की पोल खुल गई है। अंडरपास के नीचे पानी भर जाने से एक ट्रक फंस गया है, जिसमें पाइप रखे हुए हैं। ट्रक के साथ एक मशीन भी है जिस पर पांच लोग अपनी जान बचाने के लिए खड़े हुए हैं। इसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। अंडरपास में पानी भर जाने से वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप है। पानी की निकासी न होने के कारण वाहन चालक अधिकारियों को कोसते हुए दिखे। लोगों का कहना है कि हर बारिश में दिल्ली की स्थिति ऐसी ही हो जाती है, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। पीडब्ल्यूडी ने मामले का संज्ञान लेकर जल्द पानी निकलवाने को कहा है।

काफी देर तक लोगों को मजबूरी में मशीन पर बैठना पड़ा। वाहन चालकों ने इस समस्या का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। साथ ही लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को टैग किया। इसके बाद दोनों तरफ के रास्ते को वाहन चालकों के लिए बंद कर दिया गया। यूजर सचिन गुप्ता ने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि बारिश के कारण ये है जखीरा अंडरपास का नजारा। यूजर सदफ अफरीन ने ट्वीट कर लिखा कि हल्की बारिश सिस्टम की पोल खोल देती है। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेकर शिकायत दर्ज कर जल्द समस्या का समाधान करने को कहा है।

दिल्ली सरकार अपने बजट का 40% शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को देती है, वहीं केंद्र सरकार ने 2% भी नहीं दिया: संदीप पाठक

सुषमा रानी

नई दिल्ली, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने बजट 2024 को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वहीं, उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में उठाए गए मुद्दों पर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट बेहद निराशाजनक रहा है। इस बजट में सरकार ने ना तो रोजगार पर ध्यान दिया है, ना ही युवाओं और किसानों के लिए कुछ किया है। केंद्र सरकार ने इस बजट में दिल्ली और पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया है। इंडिया गठबंधन की बैठक में नीति आयोग की बैठक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत का मुद्दा भी उठा। नीति आयोग की बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से निमंत्रण तो दिया जाता है लेकिन उस बैठक में कुछ नहीं निकलता है। बैठक में बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं पर लागू एक भी नहीं होती। इस बार के बजट से केंद्र सरकार का विजन साफ दिखाई दे रहा है। केन्द्र सरकार छोटी मानसिकता के साथ काम कर रही है।

राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने आगे कहा कि आज सरकार को जगाने की जरूरत है। आप एक विशाल देश के प्रधानमंत्री हैं, इतने महान देश के प्रधानमंत्री होने के बाद इतनी छोटी विचारधारा से आप बजट बनाओगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? इंडिया गठबंधन की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। उनका शुगर लेवल बार-बार कम हो रहा है। उनका शुगर लेवल 50 से भी नीचे गिरता जा रहा है। इस तरीके से रात में शुगर लेवल कम होना किसी भी व्यक्ति की जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसपर LG साहब चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि आप यह नहीं खा रहे है, वह नहीं खा रहे हैं। एक इंसान की जान का सवाल है और आप इस तरह की घटिया मजाक कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल हुए विपक्ष के सभी नेताओं ने इसपर चिंता जाहिर की है और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।

बजट पर उन्होंने कहा कि सरकार के इस बजट का कोई लक्ष्य नहीं है। आप 10 साल से सरकार चला रहे हो तो आपके पास एक रोडमैप तो होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र को बढ़ावा देना है। आज बेरोजगारी दर 7.2 से बढ़कर 9% हो गई है।

आपका कॉर्पोरेट मुनाफा तो बढ़ गया है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ पाया है। किसानों को एमएसपी की गारंटी तो बहुत दूर की बात है आपने फर्टिलाइजर की सब्सिडी में 36 फीसदी की कमी कर दी है। भाजपा सरकार देश के किसानों से बेहद नफरत करती है। आप कॉर्पोरेट के बारे में तो सोच रहे हो लेकिन आपने किसान और युवाओं के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र से आपको कोई मतलब नहीं है। दिल्ली सरकार अपने बजट में 25 फीसदी बजट शिक्षा पर खर्च करती है, वहीं केंद्र सरकार दो फीसदी से भी कम का बजट शिक्षा क्षेत्र को देती है। आप देश के युवाओं को अनपढ़ रखना चाहते हैं। दिल्ली सरकार अपने बजट में 15 फीसदी स्वास्थ्य क्षेत्र को देती है, वहीं केंद्र सरकार एक प्रतिशत से भी कम का बजट स्वास्थ्य को देती है।

उन्होंने आगे कहा कि आयुष्मान भारत भी अन्य योजनाओं की तरह एक जुमला बनकर रह गया है। आयुष्मान भारत के लिए आप 7000 करोड़ का बजट रखते हो जबकि अकेले दिल्ली सरकार का हेल्थ बजट 9000 करोड रुपए है। यह किस तरह का भद्दा मजाक केंद्र सरकार देश के लोगों के साथ कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों से इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें बस अपनी कुर्सी बचानी है। जो केंद्र सरकार के राजनीतिक दोस्त हैं उन राज्यों को बजट में सबसे ऊपर रखा गया है। आपने गठबंधन होने के बाद ही क्यों उन राज्यों के बारे में सोचा? इससे पहले आपने उन राज्यों के बारे में कुछ क्यों नहीं किया? दिल्ली और पंजाब के साथ आपने भेदभाव किया है क्योंकि यहां पर आपके साथियों की सरकार नहीं है। अपने दिल्ली और पंजाब के हिस्से का पैसा रोक रखा है। आप किसी एक पार्टी या किसी एक राज्य के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। केंद्र सरकार ने इस बार अपनी कुर्सी को बचाने वाला बजट पेश किया है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए यह बजट बनाया है, इस बजट का देश की जनता से कोई लेना-देना नहीं है।

आम आदमी पार्टी को सरकार चलानी ही नही आती, दिल्ली सरकार चौतरफा फेल साबित हुई है: देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि पटेल नगर में यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे 26 वर्षीय नीलेश राय की बिजली का करंट लगने से हुई मौत के लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना नही है क्यांकि बारिश के बाद जल भराव के कारण बिजली के खम्बे से पटेल नगर पावर जिम के नजदीक लोहे के गेट में करंट आने के कारण नीलेश की हत्या सरकारी सिस्टम की नाकामी के कारण हुई है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि निलेश के परिवार को एक करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकारी सिस्टम की लापरवाही के कारण हुई निलेश की मृत्यु के बाद क्या उसके माता पिता को अपने बच्चे की भरपाई हो सकेगी। क्योंकि पुलिस द्वारा भी यही बयान दिया गया है कि खंबे से गेट में करंट उतरने से उसकी चपेट में आने से यूपीएससी छात्र की मौत हुई। उन्होंने कहा कि हम मृतक छात्र के परिवार के साथ खड़े है। उन्होंने

कहा कि यह दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और बिजली कंपनियों की लापरवाही के कारण हुआ है।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा बिजली कंपनियों को बेलगाम दर वसूलने की इजाजत तो दी है परंतु बिजली से सुरक्षा के लिए इंतजाम के लिए कोई दिशा निर्देश नही दिए है और हर साल बारिश के कारण जल भराव में करंट उतरने के कारण कोई न कोई मर रहा है, जिसके प्रति प्रशासन पूरी तरह असंवेनशीलता का परिचय देता रहा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के दौरान आम नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपीएससी छात्र की मृत्यु के बाद फॉरेंसिक टीम ने दौरा किया है और जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते है कि जांच सभी पहलुओं को देखकर की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सच्चाई तो यह है कि आम आदमी पार्टी को सरकार चलानी ही नही आती और सरकार हर मामले में पूरी तरह फेल साबित हुई है। हमने कई बार सर्वदलीय बैठक कराने की मांग की है परंतु सरकार दिल्ली के मुद्दों पर मिलकर नही चलना चाहती है और न ही किसी के अनुभव का फायदा लेना चाहती है। जिसके कारण दिल्ली की हालत लगातार बदतर हो रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अगर हमारी सलाह पर चले तो हम दिल्ली की सभी समस्याओं का हल हम निकाल सकते है। उन्होंने कहा कि चाहे पानी देने, बारिश का जमा पानी निकालने, बिजली कटौती अथवा लगातार बिजली की दरों में बढ़ोती का मामला हो, सरकार पूरी तरह असंवेदनशीलता और निष्क्रियता की भूमिका निभा रही है।

बजट 2024: दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए बनाया जाएगा आवास, महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा

राजधानी दिल्ली में अब काम करने वाली महिलाओं को के लिए अच्छी खबर है। अब उन सभी कामकाजी महिलाओंके लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। इसके पीछे का कारण महिला श्रम बल में इनकी भागीदारी दर बढ़ी है। 2017-18 में 23 .3 प्रतिशत थी। जो 2022-23 में बढ़कर 37 प्रतिशत तक हो गई। दिल्ली में इस समय फिलहाल 16 महिला छात्रावास हैं।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार का खासा जोर महिला सशक्तिकरण पर है। संसद में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ महिला केंद्रित कई योजनाएं लागू की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के पिटारे से भी महिलाओं के लिए कई लाभकारी घोषणाएं (Budget 2024) हुईं। उसमें से एक है कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था।

महिलाओं को सस्ता और सुरक्षित आवास ढूंढने में रहती है समस्या

यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार के प्रयासों व बदले माहौल में महिलाओं को ग्रामीण व शहरी इलाकों में रोजगार तो आसानी से मिल जाता है लेकिन सुरक्षित आवास आज भी उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में भी ऐसी महिलाओं व युवतियों की संख्या अधिक है, जो सुदूर क्षेत्रों से आकर यहां नौकरी कर रही हैं। लेकिन उन्हें रहने के लिए सस्ता व सुरक्षित आवास ढूंढने में समस्या रहती है।

23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में हुई 37 प्रतिशत

कई मामलों में इसके चलते वो अपने गृह क्षेत्र से दूर नौकरी करने में कतराती हैं। बीते वर्षों के आंकड़ों को देखे तो देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर पिछले छह वर्षों से बढ़ रही है, जो 2017-18 के 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 37 प्रतिशत हो गई है। इसलिए सरकार ने कामकाजी महिलाओं को बिना किसी समस्या के देश के किसी भी जिले में कामकाज के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित करने का निर्णय लिया है।

इस छात्रावास में कामकाजी महिलाएं सुरक्षित रह सकेंगी। केंद्र सरकार की ओर से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित करने की घोषणा से महिलाओं में काफी खुशी है। उनके मुताबिक अब वो तनावमुक्त होकर काम कर सकेंगी।

दिल्ली में फिलहाल 16 कामकाजी

महिला छात्रावास हैं। महिलाओं ने कहा कि वो चाहती हैं कि दिल्ली के हर जिले में कम से कम दो कामकाजी महिला छात्रावास हों ताकि उनको रुकने का ठिकाना ढूंढने के लिए दर-दर भटकना न पड़े। उन्हें उनके ऑफिस के नजदीक ही रहने की जगह मिल जाए।

उनके मुताबिक अभी उन्हें किराये पर कमरा लेकर रहना पड़ता है, जिसका किराया भी महंगा पड़ता है। उसमें भी हर समय उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सताती है। लेकिन कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित होने से उनकी काफी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा।

मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। दिल्ली में एक बैंक में नौकरी करती हूं। यहां आने से पहले मैंने कई छात्रावास देखे तो तंग गलियों में थे और सुरक्षा के लिहाज से भी सही नहीं थे। कमरे भी बहुत ही छोटे होते थे। बाद में मुझे एनडीएमसी के कामकाजी महिला छात्रावास की जानकारी मिली तो यहां रहने आ गई। यहां बहुत सारी सुविधाएं है, काफी बड़े कमरे हैं। मुख्य द्वार पर ही सुरक्षा गार्ड है। अकेली कामकाजी महिला के लिए दिल्ली में इस तरह के छात्रावास बहुत अच्छे हैं।
- अमरीन नाज

राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को आम पहुंचाने में क्यों हो रही देरी? बनाया जा रहा है ये बहाना

परिवहन विशेष न्यूज

राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को आम पहुंचाने में देरी की जा रही है। बहाना बनाया जा रहा है कि बारिश होने की वजह से बाग में आम नहीं तोड़ पा रहे हैं। 216 लोगों की सूची प्राप्त हो गई है इसके बावजूद भी आम नहीं पहुंचाने में देरी की जा रही है। पढ़िए आखिर पूरा मामला क्या है?

गाजियाबाद। साहिबाबाद फल व सब्जी मंडी की मंडी समिति द्वारा आम भेजने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री सहित 216 लोगों की सूची प्राप्त हो गई है।

इसके बाद भी आम भेजने में देरी की जा रही है। बहाना बनाया जा रहा है कि वर्षा की वजह से बाग में आम तोड़ने में परेशानी हो रही है। अब तक आम मंडी में पहुंच जाने चाहिए थे।

लखनऊ नवाबी शानो-शौकत के साथ ही आम के लिए भी मशहूर है। वर्ष 2005 में तत्कालीन सरकार ने लखनऊ के आम को बढ़ावा देने के लिए काकोरी ब्रांड आम (पूर्व का नाम नवाब ब्रांड) तैयार किया। बाद सहारनपुर बेल्ट का आम भी ब्रांडिंग के लिए चुना गया। निर्यात के लिए ब्रांड का प्रचार करने के मद्देनजर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रियों को आम भेजा जाता है।

इस बार भाजपा संगठन और न्यायालय से जुड़े अधिकारियों को भी आम भेजा जाएगा। मंडी समिति को तीन वर्ग में सूची प्राप्त हुई है। अलग-अलग वर्ग में 133, 25 और 58 की सूची मिली है। सहारनपुर के बागों से आम साहिबाबाद मंडी पहुंचेगा। अब तक आम मंडी में आ जाना चाहिए था, लेकिन आम पहुंचने में लगातार देरी हो रही है। आम पहुंचने में देरी का कारण मौसम को बताया जा रहा है।

विदेश निर्यात होता है आम

आम को काकोरी ब्रांड नाम से निर्यात किया जाता है। यूपी सरकार निर्यातकों और बागवानों के लिए प्रोत्साहन राशि भी देती है। काकोरी ब्रांड का आम दुबई, कुवैत, बहरीन, ओमान, अरब, जापान, अमेरिका, आस्ट्रेलिया व कतर सहित अन्य खाड़ी देशों में निर्यात होता है।

बदल दिया था आम का नाम

आम का ब्रांड नाम नवाब रखने के बाद निर्यात में कोई खास बढ़त नहीं मिल सकी। एक सीजन में कभी भी सौ से 150 मीट्रिक टन से ज्यादा आम का निर्यात नहीं हो सका। जबकि कम से कम 400 से 500 मीट्रिक टन आम का निर्यात होने की अपेक्षा की जाती है। जून 2020 में शासन स्तर पर नवाब ब्रांड का नाम बदलने पर मंथन किया गया था। अधिकारियों ने बागवानों के साथ बैठक की थी।

बागवानों से नए नाम के लिए प्रस्ताव मांगे गए थे।

वहीं, कुछ किसानों ने यूपी किंग, श्रीराम, रघुवंशी, लखन, संजीदा, अवध, दादा, निहाल, नाथ आदि नाम सुझाए थे, लेकिन नाम बदलने पर मुहर नहीं लगी। जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री ने नवाब आम का नाम बदलकर काकोरी कर दिया था। तब इस इस आम को काकोरी के नाम से जाना जाता है।

216 लोगों की प्राप्त हुई सूची

मौसम की वजह से आम अभी टूटा नहीं है। जिस वजह से आम अभी मंडी में नहीं आया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, सभी केंद्रीय मंत्री सहित कुल 216 लोगों की सूची प्राप्त हुई है। सहारनपुर से काकोरी आम मंडी में आएगा। - सुनील कुमार शर्मा, मंडी सचिव

सोलर प्लांट से रोशन होंगे गाजियाबाद के 50 हजार घर, 300 यूनिट मिलेगी फ्री बिजली

परिवहन विशेष न्यूज

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत गाजियाबाद जिले के 50 हजार घरों को रोशन किया जाएगा। इन घरों की छतों पर मार्च 2025 तक सोलर 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली दी जाएगी। इससे गर्मी में बिजली कटौती से दिक्कतों राहत मिलेगी। बजट में वित्त मंत्री ने देशभर में करीब एक करोड़ परिवारों को निशुल्क बिजली देने की बात कही है।

गाजियाबाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। इसमें निशुल्क बिजली को लेकर बड़ा एलान किया गया। इसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शामिल रही।

उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

उपभोक्ताओं का कहना है कि अगर इस योजना को जमीन पर सही ढंग से उतारा गया तो यह कारगर साबित होगी। लोगों तक योजना की जानकारी पहुंचनी चाहिए। सोलर प्लांट लगवाने से गर्मी में बिजली कटौती से दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। प्लांट लगने से बार-बार कटौती से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उपभोक्ता अपने जरूरत भर की बिजली सोलर एनर्जी के जरिए ले सकेंगे।

विद्युत निगम के अनुसार, योजना के तहत उपभोक्ता 10 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। सोलर प्लांट सरकार की ओर से निर्धारित फर्म से खरीदने पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी (अनुदान) दी जाएगी।

सोलर लगवाने के बाद कितना आएगा बिल

विद्युत निगम के मुख्य अभियंता अजय ओझा ने बताया कि एक किलोवाट घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ता का हर माह करीब 350 से 400 रुपये बिल आता है। सोलर प्लांट लगने से यह बिल महज 150 रुपये तक ही रह जाएगा। इसी तरह पांच किलोवाट वाले घरेलू कनेक्शन का बिल करीब 5000 रुपये आता है।

हरिद्वार से भटक राजस्थान पहुंची 100 वर्षीय महिला, नोएडा के उद्यमियों ने पहुंचाया झांसी

झांसी की रहने वाली महिला एक हरिद्वार में भटक गई। जब वह वापस जा रही थीं तो अपने घर के बजाय राजस्थान के सालासर के पास पहुंच गईं। यहां उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। इस दौरान नोएडा के उद्यमी मिले जिन्होंने उन्हें परेशान देखा। वहा उन्होंने महिला से बातचीत की और दिल्ली ले आए। इसके बाद उन्हें ट्रेन से वापस झांसी भेजा।

नोएडा। झांसी की रहने वाली 100 वर्षीय महिला हरिद्वार पहुंचने के बाद रास्ता भटकी और वापस झांसी पहुंचने के बजाय सालासर (राजस्थान) के पास लहोरू (हरियाणा के भिवानी जिले के पास) पहुंच गई। वहां से उन्हें ट्रेन में मिले नोएडा के उद्यमी और समाजसेवी लोगों ने दिल्ली लाकर उन्हें झांसी भेजकर उनके स्वजन से मिलाया।

पूरे प्रकरण में रेलवे की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद झांसी के कई लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और झांसी पहुंचने पर बुजुर्ग महिला अपने बेटे और स्वजन से मिल पाईं।

सालासर बालाजी से लौट रहे थे अनुज

नोएडा के उद्यमी अनुज गुप्ता ने बताया कि वह अपने मित्र कुलदीप गुप्ता, वरुण अग्रवाल, राजेश बंसल, शंकर रंगवाला और प्रखर गुप्ता के साथ सालासर बालाजी से लौट रहे थे। वह रतनगढ़ से चले थे, लहोरू से करीब 100 वर्षीय बुजुर्ग ट्रेन में महिला चढ़ी और उनकी सीट के पास आकर बैठ गईं।

हरिद्वार में साड़ी और रुपये हो गए चोरी

परेशान लग रही महिला से जब उनके बारे में और बच्चों के साथ उनके गंतव्य के बारे में पूछा तो काफी देर बाद रोते हुए बताया कि वह हरिद्वार गईं थी। वहां लक्ष्मण झूला के पास उनकी साड़ी और रुपये सहित अन्य सामान चोरी हो गया। वहां से वह किसी तरह से हरिद्वार से निकली, तो वह रास्ता भटक गईं और झांसी पहुंचने के बजाय लहोरू पहुंच गईं।

उन्होंने बताया कि उन्हें झांसी जाना है, वहां उनका घर है। घर का नाम, पता व बच्चों के नाम भी नहीं बता सकीं, लेकिन उन्होंने झांसी जाने की जिद की। उन्होंने कहा कि झांसी पहुंचने के बाद वहीं घर तक पहुंच जाएंगी। महिला के पास एक छोटे बैग में दो रोटी, दो बिस्कुट के पैकेट और 30-40 रुपये थे।

महिला को लेकर दिल्ली पहुंचे

बुजुर्ग के साथ सराय रोहिल्ला पहुंचने के बाद अनुज गुप्ता अपने मित्रों के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचे।वहां रेलवे स्टाफ द्वारा किसी प्रकार की मदद न मिलने पर झांसी जा रही ट्रेन में सेकेंड एसी की तत्काल टिकट कराई। बुजुर्ग को ट्रेन में बिठाकर अटेंडेंट को बताया कि उन्हें झांसी उतार दें।

ट्रेन रात को दो बजे झांसी पहुंची

महिला सुरक्षित झांसी पहुंच जाएं, इसके लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उनके साथ एक वीडियो बनाई और विभिन्न इंटरनेट मीडिया पर डाल दी। कुछ ही देर में झांसी के कई लोगों ने संपर्क किया। इनमें लायंस क्लब, भाजपा कार्यकर्ताओं के जीआरपी के अधिकारियों के साथ कई स्थानीय लोगों से बात हुई। ट्रेन देर रात 2 बजे झांसी स्टेशन पहुंची।

वीडियो झांसी में भी तेजी से प्रसारित हुआ, जिसका संज्ञान लेते हुए करीब 80 समाजसेवी व स्थानीय लोग महिला के बेटे को साथ झांसी रेलवे स्टेशन पहुंचे। जहां जीआरपी ने अपनी कार्रवाई करते हुए महिला को उनके बेटे के सुपुर्द किया। बुजुर्ग महिला की पहचान कोतवाली क्षेत्र के सराय मोहल्ला निवासी रमेश साहू की मां के रूप में हुई।

सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिलने पर अनुज गुप्ता ने कहा कि हमारा धर्म हमें सिखाता है कि अपने आसपास कोई भी असहाय या दुखी ना रहे। ऐसी सेवा ही ईश्वर की सेवा है।

बिल्डर ने नहीं बनाया 33 केवीए सबस्टेशन, डीसी ने दिए जमीन जब्त करने के आदेश

परिवहन विशेष न्यूज

डीसी ने बिजली निगम को बिल्डर की जमीन चिन्हित कर जिला राजस्व अधिकारी के माध्यम से जमीन जब्त करने के आदेश दिए हैं। जमीन जब्त करने के बाद 33 केवीए सबस्टेशन तैयार कर उपभोक्ताओं को दिया जाए। न्यू पालम विहार के उप मंडल अभियंता ने उपायुक्त के आदेशों की अनुपालन में जिला नगर योजनाकार तथा जिला राजस्व अधिकारी को सत्या बिल्डर की जमीन चिन्हित करने के लिए पत्र लिखा है।

गुरुग्राम। आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए लगाए जाने वाले समाधान शिविर के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। समाधान शिविर में उपायुक्त (डीसी) निशांत कुमार यादव ने 33 केवीए सबस्टेशन तैयार न करने पर सत्या बिल्डर के विरुद्ध कड़ा एक्शन लिया है।

सत्या बिल्डर ने सेक्टर-103 में सत्या हरमिटेज सोसायटी विकसित की। नियमानुसार बिल्डर को सोसायटी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए 33 केवीए सबस्टेशन तैयार करके देना था।

बिल्डर ने 11 केवीए का लिया अस्थाई कनेक्शन

बिल्डर ने बिजली निगम से 11 केवीए का अस्थाई कनेक्शन लिया और उसी के माध्यम से अभी तक सोसायटी के निवासियों को बिजली आपूर्ति की जा रही है। 11 केवीए की लाइन दौलताबाद सबस्टेशन से करीब छह किलोमीटर लंबी है। इस लाइन में अक्सर फाल्ट आने के कारण निवासियों को बिजली कटौती झेलना पड़ती है।

उपायुक्त के समाधान शिविर में की शिकायत

सत्य हेरमिटेज कंडोमिनियम एसोसिएशन के (आरडब्ल्यूए) अध्यक्ष बृजकिशोर ने 33 केवीए सबस्टेशन तैयार न करने की शिकायत उपायुक्त के समाधान शिविर में की। शिकायत में कहा कि बिजली निगम 2020 से बिल्डर को 33 केवीए सबस्टेशन तैयार कर उस पर लोड डालने के लिए पत्राचार कर रहा है।

18 मार्च 2020 को मेमो नंबर 4221 के माध्यम से, नवंबर 2020 में मेमो नंबर 6556 और मार्च 2021 में मेमो नंबर 8351 के माध्यम से बिल्डर को 33 केवीए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने को कहा गया। बिजली निगम ने 33 केवीए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बिल्डर से 32.56 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी मांगी और इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जमीन उपलब्ध कराने को कहा

बृजकिशोर ने उपायुक्त निशांत कुमार के दरबार में 33 केवीए इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला रखा। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बिजली निगम के अधिकारियों को इस मामले को जिला नगर योजनाकार और जिला राजस्व अधिकारी के माध्यम से बिल्डर की जमीन जब्त करने के आदेश दिए।

गठबंधन धर्म निभाते हुए अमृतकाल के संजोए सपने को पूरा करेगा आम बजट 2024

कमलेश पांडे

इस आम बजट को युवाओं और महिलाओं के सपनों का बजट भी करार दिया गया है। क्योंकि इनके दृष्टिगत कौशल विकास और रोजगार सृजन की जो घोषणाएं हुई हैं, वह ऐतिहासिक हैं। इस प्रकार इस बजट में पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरी तरह से झलकता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब 23 जुलाई मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया तो किसी को अमृतकाल और विकसित भारत की आहट मिली, तो किसी को वही रटी रटाई पश्चातापजो पिछले 10 सालों से होती आई है और अगले 15 सालों तक रहने वाली है, यदि इस बीच गठबंधन की गांठ नहीं खुली तो। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट बताया और कहा कि यह अगले पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। लेकिन उनकी बातों में, बजट अभिभाषण में, और बजट प्रस्तावों में मीन मेख निकालने वाले नेताओं की कमी नहीं दिखी।

बावजूद इसके केंद्रीय बजट 2024 एक संतुलित बजट है, क्योंकि इसमें महिलाओं, युवाओं, गरीबों, किसानों के हित को सामने रखकर विभिन्न आवश्यक व लोकहितकारी घोषणाएं की गई हैं। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के अमृत काल वाले विकसित भारत के संकल्प की प्रतिबद्धता को दोहराता हुआ बजट है। जिससे पूरी उम्मीद है कि यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के मिशन को पूरा करेगा। वहीं, इस केंद्रीय बजट में क्षेत्रीय असंतुलन को संतुलन में लाने की कोशिश की गई है, जो आगे भी जारी रखी जायेगी, ऐसे संकेत मिले हैं। क्योंकि देश के कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं जिन्हें पिछली सरकारों ने नजरअंदाज किया है, इसलिए विकास की गंगा वहां तक पहुंचाना समावेशी विकास की सबसे बड़ी जरूरत है।

शायद इसी नजरिए से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए की गई विभिन्न घोषणाओं से पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस लिहाज से बजट में 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है।

केंद्रीय बजट में एक तरफ आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपए और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की घोषणा की गई, जो अच्छी बात है। तो दूसरी तरफ बिहार को 26 हजार करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है। ऐसा करके वित्त मंत्री ने अपने दोनों गठबंधन साथियों टीडीपी और जदयू को साधने की पहल की है, जो समझदारी भरा कदम है। इन दोनों राज्यों के आर्थिक हितों का ख्याल रखने से एनडीए सरकार पांच सालों तक चलती रहेगी और आगे के भी चुनावों में उम्दा प्रदर्शन करती रहेगी।

इस आम बजट को युवाओं और महिलाओं के सपनों का बजट भी करार दिया गया है। क्योंकि इनके दृष्टिगत कौशल विकास और रोजगार सृजन की जो घोषणाएं हुई हैं, वह ऐतिहासिक हैं। इस प्रकार इस बजट में पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरी तरह से झलकता है। वहीं, अगर विपक्ष ने इस बजट की आलोचना की है तो इसका मतलब यह भी लगाया जा रहा है कि बजट अच्छा है, क्योंकि आलोचना करना तो उनका विपक्ष धर्म है। जिसका निर्वहन करने के लिए भी यह सरकार पूरे मौके देती है।

इस बारे में एक तरफ सत्ताधारी टीडीपी कहती है कि वाईएसआर कांग्रेस के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी दिल्ली जाकर राज्य की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के विकास और कल्याण को लेकर वित्तीय सहायता के लिए दो बार दिल्ली गए और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए 15000 करोड़ का विशेष पैकेज लेकर आए। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन की राजद सांसद और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कहती हैं कि राज्य में हत्या और चोरी हो रही है। मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है। युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही और किसानों की समस्या अभी भी जस की तस बरकरार है। ऐसे में बिहार को 26 हजार करोड़ रुपये आवंटित करना बिहार को झुनझुना देने के बराबर है।

सच कहूं तो पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक केंद्रीय बजट 2024 की आलोचना हो रही है। जहां पंजाब के संसद सदस्यों ने केंद्रीय बजट में धन आवंटन के मामले में उनके राज्य को अनदेखा करने का आरोप लगाया और विरोध प्रदर्शन तक किया। वहीं, महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने भी ताजा बजट में उनके राज्य की उपेक्षा करने का आरोप मढ़ते हुए संसद के बाहर प्रदर्शन तक किया। जबकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहलाने का गौरव प्राप्त है। बजट में महाराष्ट्र को नजरअंदाज करना भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है, क्योंकि यहां की जनता ही असली सबक सिखाएगी।

विपक्ष की इस राय में दम है कि पिछले दस वर्षों से मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि हम सिर्फ नारे सुनते रहते हैं। आज के बजट में भी जुमले ही अधिक रहे। लिहाजा, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। न तो उन्हें सरकार चलाने आता है और न ही उन्हें लोगों के दर्द से कोई मतलब है।

मौजूदा केंद्रीय बजट पर उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल के नेताओं ने जिस तरह से नाखुशी दिखाई है, उस तरह से वैकल्पिक सुझाव नहीं दिए कि इसके बदलते क्या किया जाना चाहिए। यूपी की समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ठीक ही कहा कि सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन टीम मोदी ने जो पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी बढ़ा दी है, उसके दृष्टिगत किये गए कोई ठोस उपाय नजर रही आते।

इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी मोटा आवंटन होना चाहिए था, लेकिन बजट में कुछ भी नहीं किया गया है। किचन का ध्यान तक नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार मंहगाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाह रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दो टूक कहा कि, अगर मुख्य बातें सामने आ गईं तो सरकार की पोल खुल जाएगी। क्योंकि सरकार गलत है और दिखावा कर रही है। इस बजट में कुछ भी नहीं है और यह केवल गुमराह करने वाला है।

सीधा सवाल है कि उनको मुख्य बातें सामने लाने से रोक कौन रहा है। यदि कुछ होगा, तब तो लाएंगे। उनके लाने का इंतजार रहेगा, ताकि सरकार की पोल पट्टी खुले, यदि कुछ अंदरखाने चल रहा हो तो। मोदी सरकार का पुराना इतिहास बताता है कि ये 2 करोड़ रोज़गार के वादे के साथ सत्ता में आई थी। लेकिन अब 10 साल बीत जाने के बाद चार करोड़ रोजगार पैदा करने की बात करती दिखाई पड़ी, जिसे लोग दोगुना झूठ समझते हैं। उनका तंज है, डबल इंजन की नरेंद्र मोदी की सरकार यानी डबल झूठ। इसका आशय स्पष्ट है कि यह कुर्सी बचाओ बजट है। जब पिछले दस वर्षों में बेरोजगारी दूर नहीं हुई तो अब कोई नई उम्मीद कैसे बांधी जा सकती है। हमलोग इस बारे में सिर्फ नारे सुनते रहे और आज भी बजट के जुमले ही ज्यादा मिले। लिहाजा, इस सरकार से किसी को कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि न तो उन्हें सरकार चलाने आता है और न ही उन्हें लोगों के दुःख-दर्द से कोई मतलब है। वे बजट बहुत कुछ बोलती हैं, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने क्या किया? किसानों के लिए तीन कानून लाए गए, जिसे पूर्णतया वापस लेना चाहिए। इसका स्वरूप बदलकर कभी भी उसपर अमल नहीं किया जाना चाहिए।

– :सौजन्य :–

ईवी ड्राइव द फ्यूचर

हुंडई ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु चार्ज जोन के साथ किया समझौता

परिवहन विशेष न्यूज

हुंडई मोटर इंडिया ने 24 जुलाई, बुधवार को कहा कि उसने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए चार्ज जोन के साथ समझौता किया है। इस समझौता ज्ञापन पर हुंडई के गुरुग्राम स्थित मुख्यालय में हुंडई के श्री जे वान रयू और चार्ज ज़ोन के श्री कार्तिकेय हरियाणी ने हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, चार्ज ज़ोन भारत में 100 हुंडई डीलरशिप पर डीसी 60 किलोवाट फास्ट चार्जर स्थापित करेगा।

हुंडई मोटर इंडिया ने एक बयान में कहा कि इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य देश में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार में सहायता करना है।

बयान में कहा गया है कि ये सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन सभी ईवी उपयोगकर्ताओं को शहरों और राजमार्गों पर डीलरशिप के स्थानों को ध्यान में रखते हुए अंतर-शहर और शहर के भीतर यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करेंगे।

हुंडई मोटर इंडिया के फंक्शन हेड - कॉरपोरेट प्लानिंग जे वान रयू ने कहा, ₹चूंकि भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अधिक अपनाने का लक्ष्य रखता है, इसलिए रेंज की चिंता को दूर करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने के लिए ग्राहकों की प्राथमिकता बनाने के लिए ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।₹

उन्होंने कहा कि ग्राहकों द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधानों को अपनाने में तेजी लाने और भारत के कार्बन तटस्थता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक गठबंधन महत्वपूर्ण हैं।

वर्तमान में हुंडई के 19 डीलरशिप हैं जो डीसी 60 किलोवाट सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों से सुसज्जित हैं।

लॉजिस्टिक्स ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म रोडकास्ट और एक्सेलेरेटेड मनी फॉर यू ने ईवी बेड़े प्रबंधन में क्रांति लाने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की अभूतपूर्व साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

अग्रणी SaaS आधारित लॉजिस्टिक्स ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म रोडकास्ट और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के वित्तपोषण में विशेषज्ञता रखने वाली प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) एक्सेलेरेटेड मनी फॉर यू (एएमयू) ने भारत भर में ईवी प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी साझेदारी की घोषणा की है।

इस ऐतिहासिक सहयोग के तहत एएमयू अपने द्वारा वित्तपोषित ई-रिक्शा के एक बड़े हिस्से में रोडकास्ट की उन्नत जीपीएस तकनीक को एकीकृत करेगा। यह रणनीतिक कदम ईवी संचालन में क्रांति लाने के लिए तैयार है, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में बेड़े के प्रबंधन को बढ़ाकर, सुरक्षा में सुधार करके, और लाभदायक ईवी वित्तपोषण के लिए महत्वपूर्ण क्षमता वाले उभरते बाजारों को लक्षित करना है।

रोडकास्ट ने खुद को फ्लीट मैनेजमेंट समाधानों में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है, जो जीपीएस ट्रैकिंग जैसे परिष्कृत उपकरणों का लाभ उठाता है। एएमयू जिसे ईवी अपनाने में तेजी लाने में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है, इन नवाचारों से उन्नत पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण और परिसंपत्ति प्रबंधन के माध्यम से लाभान्वित होगा। रोडकास्ट के जीपीएस उपकरणों के साथ ई-रिक्शा को लैस करके, एएमयू का लक्ष्य गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों

और भुगतान चूक से संबंधित जोखिमों की भविष्यवाणी करना और उन्हें कम करना है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषण क्षमताएं मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के प्रदर्शन में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगी, जिससे अधिक सूचित निर्णय लेने में सक्षम होगा।

रोडकास्ट के सह-संस्थापक राहुल मेहरा ने साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए कहा ₹एक तकनीक-प्रथम कंपनी के रूप में हम इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती हुई स्वीकार्यता के साथ-साथ हरित क्रांति का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एएमयू के साथ हमारी साझेदारी हमें उन्नत, कनेक्टेड ईवी तक सार्वजनिक पहुँच को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की अनुमति देती है। रोडकास्ट की जीपीएस तकनीक का एकीकरण तेजी से फंड पुनर्वितरण की सुविधा देकर एनबीएफसी को भी प्रभावित करेगा। लीजिंग समझौतों में समय पर फंड रिकवरी महत्वपूर्ण है, और हमारी तकनीक पूर्वानुमानित अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो सक्रिय जोखिम प्रबंधन रणनीतियों का समर्थन करती है। यह साझेदारी सुनिश्चित करेगी कि संभावित मुद्दों की जल्द पहचान की जाए, जिससे त्वरित हस्तक्षेप और अधिक कुशल फंड रिकवरी हो सके, जिससे अंततः ईवी क्षेत्र में वित्तीय संचालन और स्थिरता में सुधार हो सके।"

एएमयू के संस्थापक और प्रबंध निदेशक नेहल गुप्ता ने इस सहयोग के बारे में उत्साह व्यक्त करते हुए कहा ₹हमें रोडकास्ट के साथ साझेदारी करके खुशी हो रही है। यह सहयोग मुख्य रूप से हमें डिफॉल्ट के जोखिम वाले वाहनों की पहचान करने में मदद करेगा, जिससे प्रभावी हस्तक्षेप और सुव्यवस्थित फंड आवंटन संभव होगा। रियल-टाइम वाहन ट्रैकिंग में रोडकास्ट की IoT विशेषज्ञता सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाएगी, जिससे कुशल EV और UAV संचालन को समर्थन मिलेगा। यह साझेदारी न केवल पर्यावरण के अनुकूल परिवहन और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ावा देती है, बल्कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान देने के एएमयू के दृष्टिकोण के अनुरूप भी है। वित्तपोषित वाहनों की सुरक्षा और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करके, एएमयू विश्वास को बढ़ावा दे सकता है, छोटे व्यवसायों का समर्थन कर सकता है और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में स्थायी प्रथाओं को आगे बढ़ा सकता है।"

सरकार हाईवे के किनारे लगाएगी 5800 चार्जिंग स्टेशन

परिवहन विशेष न्यूज

अब आप हाईवे पर बिना रुके इलेक्ट्रिक वाहन चला सकेंगे। सरकार ने अब 7,432 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 5,833 हाईवे के किनारे लगाए जाएंगे। यह जानकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आज बुधवार 24 अप्रैल को दी। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों की कुल संख्या 5,293 है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि तीनों सरकारी तेल वितरण कंपनियों को 7,432 चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 800 करोड़ रुपये की पूंजी सहायता दी जाएगी। मौजूदा 5,293 ईवी चार्जिंग स्टेशनों में से 4,729 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत स्थापित किए गए हैं, जिसमें करीब 178 करोड़ रुपये का खर्च आया है। गडकरी ने अपने बयान में कहा कि भारी उद्योग मंत्रालय ने 7,432 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 5,833 ईवी चार्जिंग स्टेशन राजमार्गों के किनारे स्थापित किए जाएंगे। ये चार्जिंग स्टेशन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाली तीन तेल वितरण कंपनियों के जरिए लगाए जाएंगे।

नितिन गडकरी ने अपने भाषण में आगे कहा कि फिलहाल सरकार ने ईवी चार्जिंग स्टेशन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कोई बिजली स्टेशन बनाने की कोई योजना नहीं बनाई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 750 ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 577, राजस्थान में 482, तमिलनाडु में 369, कर्नाटक में 300 और हरियाणा में 284 ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं।

ग्रीन मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली 500 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) 2024 को 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक लागू किया गया है। इस योजना के लिए 493.55 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू विनिर्माण को समर्थन मिलेगा। इस योजना में प्रोत्साहन का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। वित्त वर्ष 2025 में दोपहिया वाहन उद्योग 7 से 9 फीसदी की दर से बढ़ सकता है। केयरएज रेटिंग्स के मुताबिक सरकार की ईएमपीएस योजना की वजह से चालू वित्त वर्ष में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में वृद्धि जारी रहेगी।

ई-रिक्शा यानी एल-3 सेक्टर को बजट 2024 से नहीं मिला कोई लाभ

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्रीय बजट 2024-25 में ई-रिक्शा उद्योग को कुछ खास नहीं मिला। 2014 से ई-रिक्शा ने इस क्षेत्र में ईवी विकास को गति देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन ई-रिक्शा उद्योग गुणवत्ता और शोध पर ध्यान न देकर सरकार को आकर्षित करने में विफल रहा है। जिसका खामियाजा आज पुराने निर्माताओं के साथ-साथ छोटे और मध्यम स्टार्टअप को भी उठाना पड़ रहा है।

ई-रिक्शा क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक योजना न होने पर निर्माताओं ने सरकार को निराश किया हैं। 2019 में शुरू किए गए फेम के दूसरे चरण के मिले-जुले नतीजे मिले। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों ने लक्ष्य को पार कर लिया, जबकि इलेक्ट्रिक बसें और तिपहिया वाहन पीछे रह गए।

सरकार का ध्यान अब बसों और ट्रकों जैसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर जा रहा है। जैसे-जैसे ईवी परिदृश्य विकसित हो रहा है, उद्योग अपनाने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी समर्थन तंत्र पर स्पष्टता का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।

ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स और पीएचएफ लीजिंग फाइनेंस में हुआ समझौता, डीलर और ग्राहकों को मिलेगा लाभ

परिवहन विशेष न्यूज

ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स और पीएचएफ लीजिंग फाइनेंस ने बड़ी साझेदारी की है। कंपनियों की बीच हुई यह साझेदारी जहां डीलर फाइनेंस को सीधे इंपैक्ट करेगा। वहीं यह साझेदारी अप्रत्यक्ष रूप से ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स ग्राहकों के लिए भी हितकारी साबित होगी। ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स ने अपने डीलरों को सप्लाई चेन फाइनेंस सॉल्यूशन देने के लिए पीएचएफ लीजिंग फाइनेंस के साथ भागीदारी की है। कंपनी के बयान के मुताबिक डीलरो को अब कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के सप्लाई चेन फाइनेंस के लिए पीएचएफ लीजिंग फाइनेंस का साथ मिलेगा।

ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स के डायरेक्टर जितेंद्र ठुकराल ने बताया कि दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार ठुकराल इलेक्ट्रिक और पीएचएफ लीजिंग फाइनेंस आपस में अपने व्यापक नेटवर्क का इस्तेमाल कर व्यापार बढ़ाएगी। इस सहयोग में दोनों कंपनियों का हित शामिल है। कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध है। पीएचएफ लीजिंग फाइनेंस के साथ हुई यह साझेदारी ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स के डीलर पार्टनर्स को जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और डीलरों को कार्यशील पूंजी तक पहुंच मिल पाएगी।

कंपनी के इशांक सुनेजा ने बताया कि इस फाइनेंसिंग प्रोग्राम के जरिए बढ़ते इलेक्ट्रिक कमर्शियल पैसेंजर व कार्गो वाहन व्यवसाय का सीधा लाभ उठा सकेंगे। इस सहयोग से डीलरों को लाभ होगा और भारत में ईवी मोटर वाहन इंडस्ट्री के विकास को भी गति मिलेगी।

हर्बालाइफ और शिशु मंदिर ने ईको-व्हील्स महिला पहल शुरू की, ई-ऑटो के साथ 115 महिलाओं को बनाया सशक्त

परिवहन विशेष न्यूज

हर्बालाइफ ने शिशु मंदिर के साथ मिलकर बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में ₹ईको-व्हील्स विमेन इनिशिएटिव₹ की शुरुआत की, जो महिला सशक्तिकरण और स्थायी आजीविका की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हर्बालाइफ इंडिया के प्रबंध निदेशक अजय खन्ना ने लाभार्थियों को 50 ई-ऑटो भेंट किए। इस कार्यक्रम में महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक श्रीमती मंजुला अरविंद लिंबावली और शिशु मंदिर की संस्थापक डॉ. हेला मुंद्रा की गरिमामयी उपस्थिति रही।

"ईको-व्हील्स महिला पहल" का उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता और कौशल विकास के अवसर प्रदान करके हाशिए पर पड़ी महिलाओं का समर्थन करना है। ई-ऑटो परियोजना के लाभार्थी वे महिलाएँ हैं जिन्होंने गंभीर दुर्व्यवहार या परित्याग को सहन किया है, विधवा हैं या अपने बच्चों के लिए ज़रूरतें भी पूरी करने के लिए संघर्ष करती हैं। इन लचीली महिलाओं में एकल माताएँ, शराबियों और दुर्व्यवहार करने वालों की पत्नियाँ और पर्याप्त आश्रय के बिना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाएँ शामिल हैं।

अजय खन्ना ने शिशु मंदिर के मिशन के लिए हर्बालाइफ के अटूट समर्थन की पुष्टि की तथा टिकाऊ और प्रभावशाली सीएसआर पहलों के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम के लाभार्थियों ने अपने परिवर्तनकारी अनुभव साझा किए तथा बताया कि किस तरह इस पहल ने उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने और गरीबी रेखा से नीचे की स्थिति से ऊपर उठने में मदद की है।

हर्बालाइफ़, जो अपनी धर्मार्थ पहलों के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है ने 115 ई-ऑटो प्रायोजित किए हैं। यह सहायता वाहनों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि उन्होंने 50 महिला ड्राइवरों के प्रशिक्षण को भी प्रायोजित किया है, जिससे उन्हें अपने लाइसेंस सुरक्षित करने में मदद मिली है। इसके अतिरिक्त हर्बालाइफ़ ने स्कूली बच्चों को टी-शर्ट, पानी की बोतलें और बक्से जैसी आवश्यक वस्तुओं के साथ सहायता की है, जिससे उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ कम हुआ है।

इस साझेदारी पर बोलते हुए हर्बालाइफ इंडिया के प्रबंध निदेशक अजय खन्ना ने कहा, ₹हर्बालाइफ में हमारी सीएसआर पहलों के माध्यम से समुदायों को ऊपर उठाने की हमारी प्रतिबद्धता बहुत ही व्यक्तिगत है। प्रत्येक परियोजना हमें उस प्रभाव के करीब लाती है जिसे हम बनाना चाहते हैं। ईको व्हील्स विमेन पहल अपने दोहरे फोकस के लिए जानी जाती है, क्योंकि यह महिलाओं को सशक्त बनाती है और पर्यावरणीय स्थिरता को अपनाती है। हम विविधता और समावेशिता के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह परियोजना 115 से अधिक महिलाओं और LGBTQ व्यक्तियों को सक्षम बनाती है, उन्हें आर्थिक स्थिरता और स्वतंत्रता प्रदान करती है। अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रिक ऑटो पेश करके, हम उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों के साथ संरेखित है। जैसा कि हम भारत में 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हम और अधिक परियोजनाएँ शुरू करने के लिए समर्पित हैं जो परिवारों को गरीबी से ऊपर उठाती हैं और समुदाय में सकारात्मक बदलाव को प्रोत्साहित करती हैं।"

शिशु मंदिर के निदेशक श्री आनंद सी ने कहा, ₹हमारा ई-ऑटो कार्यक्रम हाशिए पर पड़ी महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आशा की किरण है। इन व्यक्तियों में हम जो परिवर्तन देखते हैं, वह बहुत गहरा है, जो निराशा से गरिमा और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस यात्रा में हर्बालाइफ का अटूट समर्थन महत्वपूर्ण रहा है और साथ मिलकर हम स्थायी परिवर्तन ला रहे हैं। हमारी साझेदारी सामाजिक प्रभाव और सामुदायिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में सहयोग की शक्ति का उदाहरण है। हम इस यात्रा को जारी रखने और भविष्य में और अधिक लोगों के जीवन को छूने के लिए तत्पर हैं।"

13 अप्रैल, 2022 को कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से ई-ऑटो ड्राइवरों के आठ बैचों को प्रशिक्षित किया गया है और प्रत्येक बैच की संख्या बढ़ती जा रही है। शिशु मंदिर के सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्येक आवेदन की सावधानीपूर्वक जाँच करते हैं और यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल वास्तव में ज़रूरतमंद लोगों को ही सहायता मिले। कठोर प्रशिक्षण सत्र शुरू होते हैं, जो कार सिम्युलेटर अभ्यास से शुरू होते हैं और कुशल प्रशिक्षकों के साथ व्यावहारिक अभ्यास तक आगे बढ़ते हैं। सड़क पर आने के बाद निरंतर समर्थन कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करता है और नियमित रखरखाव कार्यशालाएँ ई-ऑटो को अच्छी स्थिति में बनाए रखती हैं। 87 से अधिक महिलाएँ अब गर्व से इन ई-ऑटो को चलाती हैं, जो एक ऐसे कार्यक्रम की सफलता का प्रतीक है जो निरंतर सहायता नेटवर्क के माध्यम से उनकी समग्र आवश्यकताओं का पोषण करता है।

शिशु मंदिर ड्राइविंग स्कूल महिलाओं को चार पहिया वाहन चलाने का प्रशिक्षण देता है, जिससे वे ई-ऑटो या कैब ड्राइवर बन सकती हैं। शिशु मंदिर प्रत्येक महिला को 50 घंटे का प्रशिक्षण देता है, जिसमें उन्हें Google मैप्स का उपयोग करके शहर में नेविगेट करना सिखाया जाता है। इसका लक्ष्य एक वर्ष में 100 महिलाओं को सशक्त बनाना है। वर्तमान में 50 महिलाएँ जिन्हें प्रशिक्षित किया गया है और जिन्होंने अपने लाइसेंस प्राप्त किए हैं, वे कम वेतन वाली नौकरियों से ई-ऑटो चलाने के लिए संक्रमण की प्रतीक्षा कर रही हैं। संगठन का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष के अंत से पहले अन्य 50 महिलाओं को प्रशिक्षित करना है और उनके लिए ई-ऑटो खरीदने के लिए समर्थन चाहता है। 50 महिलाओं को प्रशिक्षित करने की लागत लगभग 5,00,000 रुपये है, जिसमें प्रशिक्षकों का वेतन और ईंधन, प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली मौजूदा कारें शामिल हैं। इस वित्तीय वर्ष के लिए शिशु मंदिर 150 ई-ऑटो खरीदने के लिए हर्बालाइफ़ के समर्थन की प्रतीक्षा कर रहा है।

पिछले पांच सालों में शिशु मंदिर ड्राइविंग स्कूल ने 900 से ज़्यादा पुरुषों और महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। कोविड के बाद ध्यान महिलाओं की ओर गया। शुरू में ड्राइविंग की नौकरी करने में अनिच्छुक, रोटरी क्लब के सहयोग से खरीदे गए पहले पाँच ई-ऑटो की सफलता से प्रोत्साहित होकर ज़्यादा महिलाएँ आगे आने लगी हैं। वर्तमान में दो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित 17 महिलाएँ शिशु मंदिर द्वारा प्रदान किए गए ई-ऑटो चलाती हैं।

शिशु मंदिर ऑटो पर डोनर ब्रांडिंग सुनिश्चित करता है, जिसमें निर्माण कंपनी द्वारा एक वर्ष की निःशुल्क सर्विसिंग प्रदान की जाती है। रखरखाव लागत न्यूनतम है और महिला संगों के माध्यम से एक बचत योजना ड्राइवरों को बैटरी प्रतिस्थापन जैसी भविष्य की जरूरतों के लिए बचत करने में मदद करती है। ई-ऑटो ड्राइवर के नाम पर पंजीकृत हैं, जिससे वे इसके असली मालिक बन जाते हैं। बीमा, कर और अन्य प्रशासनिक कार्य शिशु मंदिर द्वारा वहन किए जाते हैं। शिशु मंदिर परिसर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं और महिंद्रा के सहयोग से और अधिक स्टेशन स्थापित करने की योजना है।

महिलाएँ, जो पहले 10,000 रुपये प्रति माह से भी कम कमाती थीं, अब लगभग 30,000 रुपये प्रति माह कमाती हैं, जिससे वे अपने रहने की स्थिति में सुधार कर सकती हैं और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकती हैं। ई-ऑटो पर्यावरण के अनुकूल हैं, जो उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। महिला ड्राइवरों को सुरक्षा के लिए प्राथमिकता दी जाती है, खासकर स्कूली बच्चों को ले जाने और बुजुर्ग यात्रियों को मेडिकल अपॉइंटमेंट में मदद करने के लिए।

महिंद्रा के 3-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों ने CO_2 उत्सर्जन और ईंधन की महत्वपूर्ण मात्रा में बचत की है, जिससे भविष्य में हरियाली लाने में मदद मिली है। प्रत्येक ई-ऑटो उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में योगदान देता है।

इस पहल के प्रत्यक्ष लाभार्थियों में 115 महिलाएं और उनके परिवार शामिल हैं, जिनकी कुल संख्या लगभग 750 है। अगले पांच वर्षों में, ये परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएंगे और सामूहिक रूप से 1,80,000,000 रुपये कमाएंगे। अप्रत्यक्ष लाभार्थियों में वे लोग शामिल हैं जो इन ई-ऑटो का उपयोग करते हैं, जो महिला ड्राइवरों द्वारा ड्राइविंग को पेशे के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित हैं, जो संभावित रूप से आने वाले वर्षों में 1,500 से अधिक महिलाओं को प्रेरित कर सकते हैं।

लोकतंत्र और राजनीतिक हिंसा

डा. वरिंद्र भाटिया

राजनीतिक हिंसा के माहौल में मानव अधिकारों का उल्लंघन, जैसे कि पीड़ा, गायब होना और न्यायेतर हत्याएं, आम बात हो जाती हैं। इसके अलावा राजनीतिक हिंसा के अंतराष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं। हिंसा रोकने को व्यापक दृष्टिकोण चाहिए'

प्रधानमंत्री जी और विपक्ष के नेताओं ने अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है और कहा कि राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा का उमड़ता प्रभाव पूरे विश्व के लिए चिंताजनक है। आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक पेपर के मुताबिक लोकतंत्र और हिंसा का अपवित्र और गहन संबंध है। यहां तक कि दुनिया के सबसे परिपक्व लोकतंत्र भी इस तरह के गहरे संबंध को खत्म करने में असमर्थ रहे हैं। उदाहरण के लिए 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 2000 के दशक के बीच ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली और जर्मनी जैसे पश्चिमी यूरोप के देशों में चरमपंथी समूहों की ओर से राजनीतिक हिंसा का विस्फोट देखा गया। हाल के वर्षों में, दुनिया ने यूनाइटेड किंगडम (यूके) में ब्रेक्सिट मुद्दे, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन और 2020 और 2024 के अमरीकी चुनावों पर राजनीतिक हिंसा की घटनाएं देखी हैं। भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी राजनीतिक हिंसा से कभी अलग नहीं रहा है। जहां तक देशी लोकतंत्र के राजनीतिक कटु सत्य का सवाल है तो भारत में लोकतांत्रिक शासन की जो प्रणाली विकसित हुई है, चाहे कोई माने या न माने, वह अब सेवा की बजाय सत्ता और शक्ति केंद्रित हो गई है। पश्चिम के विकसित देशों में जनप्रतिनिधि लोगों की सेवा करने के लिए चुने जाते हैं, जबकि भारत में लोगों पर शासन करने के लिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं।

चुनाव जीतने पर मिलने वाली असीमित सत्ता और पैसा समूची राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया को किसी न किसी रूप में भ्रष्ट और हिंसक बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में हिंसक राजनीतिक संघर्ष अक्सर देखने को मिलते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था कमाल की है। आज भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था के उपलब्ध तरीकों में से एक बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योंकि यह बुनियादी मानवीय मूल्यों के आधार पर पनपता है।

लोकतंत्र का मतलब होता है जवाबदेही के साथ समाज के हित में समाज के साथ मिलकर निर्णय लेना और उन्हें लागू करना।

वैसे तो देश चलाने के लिए कई तरह की व्यवस्थाओं के विकल्प मौजूद रहे हैं, लेकिन उन सबमें लोकतंत्र को सबसे बेहतर व्यवस्था माना गया है, क्योंकि इस व्यवस्था में अलग-अलग विचारों, मतों, परिस्थितियों को ध्यान में रख कर निर्णय लिए और लागू किए जाते हैं। यह केवल संख्याओं या बहुमत से चलने वाली व्यवस्था नहीं है। बहुमत के निर्णय को लागू करने से पहले यह देखना होता है कि व्यापक समाज के हित में क्या है? कहीं इससे अन्याय तो नहीं हो रहा है? कहीं किसी के साथ भेदभाव या शोषण तो नहीं हो रहा है? याद रहे कि लोकतंत्र में मूल्यों, उसूलों, मानकों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अगर बहुमत वाली व्यवस्था मूल्यों से भटक कर निर्णय लेने लगे, तो परिवार, समाज और देश को बहुत नुकसान पहुंचता है। लोकतांत्रिक समाज ज्यादा गहरा और स्थिर होता है। अगर कभी देश के ऊपर कोई संकट आता है, तब लोकतांत्रिक समाज इससे निपटने का काम केवल सरकार पर नहीं छोड़ देता है, बल्कि लोग खुद भी समाधान खोजने में जुट जाते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की मौजूदगी का एक बड़ा कारण संवादहीनता भी है। लोकतंत्र की पहली और सबसे बड़ी जरूरत संवाद है। यह एक ऐसा भावनात्मक तत्व होता है, जो लोगों को जोड़ता है। संवाद से ही एक-दूसरे के प्रति स्वीकार्यता पैदा होती है। जब भी लोकतंत्र को तोडना होता है, तब सबसे पहले संवाद को तोड़ा जाता है। कोई भी व्यक्ति जब अपना मत व्यक्त करता है, तब हिंसा से, डर से, भय से, दबाव से उसे अपना मत वापस लेने के लिए मजबूर किया जाता है।

यही राजनीतिक हिंसा का मूल तत्व होता है। आज अमरीकी लोकतंत्र को लेकर हमारी सोच सवालिया निशान लगा रही है। असल में डोनाल्ड ट्रंप पर हमला अमरीका में नफरत की बुनियाद पर बनाए जा रहे अमरीकी समाज की भयानक तस्वीर है। एक ताजा अमरीकन सर्वे में पाया गया कि 10 प्रतिशत लोग बल प्रयोग के जरिए भी ट्रंप को रास्ते से हटाने के पक्षधर हैं, तो 7 प्रतिशत ऐसे लोग भी हैं जो हर ताकत का इस्तेमाल कर ट्रंप को सत्ता में लाने के समर्थक हैं। यह रस्साकशी भी वहां राजनीतिक हिंसा के लिए एक कारक हो सकती है। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबर्ट पेप, जो शिकागो प्रोजेक्ट ऑन सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स के डायरेक्टर भी हैं, ने नेशनल सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि 10 प्रतिशत अमरीकी वयस्क नागरिक, जिनमें से एक-तिहाई के पास बंदूकें हैं, वो इस बात से सहमत हैं कि 'डोनाल्ड ट्रम्प को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए बल का प्रयोग उचित है।' लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की मौजूदगी किसी भी शासकीय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। भारत में हो रही पॉलिटिकल किलिंग्स की संख्या चिंताजनक है। देश में 2017 से 2019 के बीच, यानी महज दो साल के भीतर करीब 230 हत्याएं राजनीतिक कारणों से हुईं। इनमें सबसे अधिक 49 हत्याएं झारखंड में हुईं। इसके बाद 27 हत्याएं पश्चिम बंगाल में हुईं और 26 हत्याएं बिहार में हुईं। ये आंकड़े सरकार ने लोकसभा में रखे थे। केरल में भी राजनीतिक हत्याओं के खूब मामले सामने आए हैं। 2006 से 2021 के बीच 125 पॉलिटिकल मर्डर हुए। इनमें से 30 मर्डर तो 2016 से 2021 के बीच ही हो गए। पश्चिम बंगाल में भी बीते कई सालों से स्थिति चिंताजनक है। पूरे विश्व में राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए राजनेताओं को आगे आना होगा। मीडिया की शिक्षा में 'टू स्टेप फलो मॉडल' नाम की थ्योरी पढ़ाई जाती है। इस थ्योरी में कहा गया है, 'मास मीडिया के मुकाबले लोग ओपिनियन लीडर्स (नेता) की बातों से प्रभावित होते हैं।' इसलिए राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए यह भी कहना जरूरी है कि विश्व के समस्त राजनेता संयम के साथ शब्दों का इस्तेमाल करें।

राजनीतिक हिंसा के व्यक्तियों, समुदायों और समाजों पर दूरगामी परिणाम होते हैं। यह सामाजिक सामंजस्य को कमजोर करती है, संस्थाओं में विश्वास को कम करती है और राजनीतिक स्थिरता को बाधित करती है।

इसके प्रभाव तत्काल और दीर्घकालिक दोनों हो सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर, राजनीतिक हिंसा से जान-माल की हानि, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आघात, विस्थापन और आजीविका में व्यवधान होता है। हिंसा से प्रभावित समुदाय सामाजिक विभाजन, अविश्वास और टूटे हुए रिश्तों का अनुभव करते हैं। आर्थिक गतिविधियां अक्सर बाधित होती हैं, जिससे गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक गिरावट आती है। राजनीतिक हिंसा का शासन और मानवाधिकारों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यह कानून के शासन को चुनौती देती है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है। राजनीतिक हिंसा के माहौल में मानव अधिकारों का उल्लंघन, जैसे कि पीड़ा, गायब होना और न्यायेतर हत्याएं, आम बात हो जाती हैं। इसके अलावा राजनीतिक हिंसा के अंतरराष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं। यह क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे सकती है, शरणार्थियों के प्रवाह को बढ़ा सकती है और उग्रवाद-आतंकवाद के लिए प्रजनन आधार प्रदान कर सकती है।

राजनीतिक हिंसा के अतिशय प्रभाव पड़ोसी देशों को बाधित कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को खराब कर सकते हैं और शांति निर्माण के प्रयासों में बाधा डाल सकते हैं।

राजनीतिक हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो इसके मूल कारणों से निपटे और स्थायी शांति को बढ़ावा दे। कानून का शासन मजबूत हो और संवाद-सुलह को बढ़ावा मिले।

संपादकीय

अब संघ वर्जित नहीं

अब सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस के सदस्य बन सकेंगे। अभी तक इस पर पाबंदी थी। 30 नवंबर, 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी को एक ही श्रेणी में रखकर पाबंदी लगाई थी। यानी इतना कट्टरपंथी और सांप्रदायिक हिंसावादी करार दिया गया था। ऐसे ही ऑफिस मेमोरेंडम (एमओ) 1970 और 1980 में भी जारी किए गए थे। तब भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थीं। करीब 58 साल के बाद इन एमओ की समीक्षा की गई और आरएसएस का नाम हटा दिया गया। संघ पर से पाबंदी हटा दी गई। नतीजतन किसी भी स्तर का सरकारी कर्मचारी अब घोषित तौर पर संघ का सदस्य बन सकता है। सार्वजनिक रूप से संघ की शाखाओं में भी शामिल हो सकेंगे। संघ के समारोहों और अभियानों में भी शिरकत कर सकेंगे। संघ पर पाबंदी नहीं रही, लेकिन संघ की सोच और विचारधारा के सरकारी कर्मचारी छिप-छिप कर शाखाओं में तो जाते थे। ऐसा हमारा पुराना अनुभव रहा है। संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक राष्ट्रवादी, सामाजिक संगठन है, जिसके 5.85 लाख सदस्य बताए जाते हैं। देश भर में संघ की 60,000 से अधिक शाखाएं हररोज लगती हैं। संघ राष्ट्रवादी, हिंदूवादी है, लेकिन अतिवादी नहीं हो सकता। यह एहसास देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार पटेल को हुआ, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में आरएसएस पर पाबंदी थोप दी थी। 1948 में पाबंदी और 1949 में पश्चातापनतीजतन पाबंदी हटा ली गई। ऐसा ही एहसास तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को हुआ, जिन्होंने भारत-चीन युद्ध के बाद पहले गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी के राष्ट्रीय आयोजन के अवसर पर संघ को आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में पूरे देश को आपातकाल में झोंक दिया था, लिहाजा संघ कैसे बच सकता था? वह पाबंदी 1977 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान हटाई गई। 1992 में अयोध्या विवाद की हिंसा के मद्देनजर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भी संघ पर पाबंदी चस्पा की, लेकिन 4 जून, 1993 को उसे वापस भी ले लिया।

आरएसएस पर प्रतिबंध लगते रहे हैं और उसे अतिवादी, उग्रवादी भी समझा जाता रहा है, लेकिन उसका राष्ट्रवाद कइयों की समझ से परे है। संघ सनातनवादी सोच का भी है, लेकिन मुसलमान को भी एक ही डीएनए की प्रजाति मानता है, लिहाजा वह तिरस्कृत नहीं है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल सत्ता में रहने के बाद संघ की वर्जनाओं को समाप्त किया है, सरकारी कर्मचारियों के प्रवेश के रास्ते खोले हैं, लिहाजा इस निर्णय पर भी सवाल किए जा रहे हैं। संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं। नाराज संघ को मनाने की कोशिश बताया जा रहा है। कांग्रेस समेत विपक्ष ने इस निर्णय को 'संविधान के खिलाफ' करार दिया है और सरकारी दफ्तरों, संस्थानों पर संघ के कब्जे की परोक्ष कोशिश माना है। आरएसएस का मानना है कि नया फैसला और पाबंदियों से मुक्ति भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही मजबूत करेगी। संघ की स्थापना 1925 में की गई थी, लिहाजा यह संघ का शताब्दी-वर्ष है। इतने लंबे दौर में संघ ने खुद को जिंदा और प्रासंगिक रखा है, यह संघ का अनुशासन और संगठन ही है। आम धारणा है कि सरकारी कर्मचारी को किसी भी संगठन या राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं बनने दिया जाए, क्योंकि उससे तटस्थता, ईमानदारी, निष्पक्षता प्रभावित होती हैं। सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल, 1964 में सभी नियम दिए गए हैं कि सरकारी कर्मचारी का संगठनों में शामिल होने का आचरण क्या होना चाहिए।

नया एमओ 9 जुलाई को कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। बीते कुछ अरसे से संघ और भाजपा के संबंधों में फासले आए थे। वैसे यह संबंध मां-बेटी का है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने बयान दिया था कि अब भाजपा को संघ की इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी अपने शुरुआती दौर में थी। इस बयान की व्याख्याएं ऐसे की गईं कि अब भाजपा खुदमुख्तार हो गई है। संघ और भाजपा में दरारों की भी बात कही गई। सत्य इससे कोसों दूर रहा है।

राय

सुख के सपनों का दुख

विजय गर्ग

कहते हैं कि सुख और दुख जीवन में परछाई की तरह होते हैं। दोनों का समय बंधा हुआ है। आज दुख है तो कल सुख हमारे द्वार आएगा। जो आज सुखी है, उसके जीवन में दुख चुपके से प्रवेश कर जाएगा। दुख के अर्थ अनेक हैं। वह हमारी सेहत का हो सकता है। वह रोजगार को छीन सकता है, रिश्तों में खटास ला सकता है या दुख हमारे सपने को तोड़ सकता है। मगर सुख की एक परिभाषा है चेहरे पर मुस्कराहट जो आदमी प्रसन्न है, वह सुखी है और जो सुखी है वह प्रसन्न है। इससे इतर एक और सवाल मन में आता है कि आखिर दुख क्यों उपजता है? शायद किसी साधारण व्यक्ति के लिए एक परिभाषा हो सकती है कि जब अपने मन का न हो तो दुख, लेकिन हकीकत यह है कि दुख से बड़ा दुख सुख के सपने देते हैं। हम सपने बुन लेते हैं। कई बार हमारे जीवन में यह सपना आता है कि हमारी शिक्षा के मुताबिक ओहदा और सम्मान मिले, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है और हम दुखी हो जाते हैं। यहां दुख की परिभाषा बदल जाती है, क्योंकि सुख के सपने की कल्पना पूरी नहीं होने पर हम दुखी हो जाते हैं।

ऐसे लोग आसपास देखे जा सकते हैं, जिनकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं रही, लेकिन आज वे खुश हैं। यह खुशी उनके सपनों के सच हो जाने की खुशी है। जिस जीवनसाथी से जीवन भर उनकी नहीं बनी होगी, अचानक उनके प्रति चिंता या उनके हवाले खुद को छोड़ देना सुख नहीं है, बल्कि सुख के सपनों को पूरा करना है। एक सच यह भी है कि जब उस दंपती के बीच जीवनभर तनातनी चल रही होगी, तब वे आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं रहे होंगे। सत्ता संस्थानों और ख्याति की कल्पना की जाती है, उससे भी बहुत वास्ता नहीं होगा। मगर जीवन का पहिया घूम जाए तो और सुख के सपने सच होने लगते हैं। धन, सत्ता और ख्याति पास चली आती है। और फिर सुख भी पहलू में आ जाते हैं। दुख का सुख में बदलना शायद इसे ही कहते हैं।

हम जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं, उसमें अगर किसी महिला जीवनसाथी को यह कहा जाए कि पति के जिंदा और स्वस्थ रहने की इच्छा अपने जीवन के अनावश्यक कष्टों की आशंका की वजह से की जाती है, तो यह शायद आम धारणा के मुताबिक ही होगा और महिला जीवनसाथी इसे सच भी माने। निर्भरता की स्थितियां कई बार इस तरह सोचने पर मजबूर करती हैं। इस तरह की बातों में सुख और दुख का दोनों पलड़ा समान है, क्योंकि महिला के सुख के सपने टूट नहीं रहे हैं और दुख की आशंका को उसने जाहिर कर दिया है। हमारे समाज में अनेक परिवार हैं जिनमें लोग गफलत में ही सही, सुख के सपने के साथ जीवन बसर कर लेते हैं। अगर रिश्ते के लिए सोचा और किया जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। मगर यह कहा जाए कि कोई पैसे के लिए उसका खयाल रख रहा है तो इस तरह का दंभ जीवन में एक नया दुख दे सकता है।

दुख को सुख के सपनों में परिवर्तित करने का एक अवसर तब आता है, जब बच्चे उनका साथ छोड़कर अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं। एकाकीपन में जो साथ होता है, वह सुख और दुख की किसी परिभाषा से परे होता है। यहां परस्पर जरूरत दोनों को साथ लेकर आता है। खाना से लेकर दवा तक इंतजाम करना होता है और यही जरूरतें सुख और दुख की नई परिभाषा गढ़ती हैं। इसे हम अपने अनुरूप अपनी परिभाषा में ढाल सकते हैं।

सुख के सपने टूटने का मनोवैज्ञानिक कारणों का पता लगाया जाए तो बेहताशा उम्मीदों का टूट जाना और निराशा में मौत को गले लगाना है। देश के किसी भी राज्य में खुदकुशी के आंकड़े देखे जाएं तो सर्वाधिक निराश और हताश युवा मिलेंगे जो जीवन को खत्म करना सबसे आसान समझते हैं। उनका जीवन अभी शुरू हुआ है और उनके जीवन में अच्छे अंकों से पास नहीं होना या मनमर्जी के मुताबिक नौकरी नहीं मिलना या बेरोजगारी से तंग आकर प्रेम का टूट जाना उनका दुख है। यह वही स्थिति है जहां दुख ने नहीं, सुख के सपनों ने हमेशा इस पीढ़ी को दुखी किया है। ऐसे में पिता का पीठ पर हाथ और मां का दुलार उन्हें ऐसे दुख से उबार सकता है। यहां दुख और निराशा में भी भेद करने आना चाहिए। दुख आने पर इसका निदान हो सकता है, लेकिन निराशा का कोई मरहम नहीं. आज समाज में ऊंचे सपने और टूटते सपनों के बीच युवा मन टूट रहा है। एक पुरानी लोककथा है, जिसमें पिता-पुत्र बाजार से निकलते हैं और पुत्र हाथी देखकर मचल उठता है। गरीब पिता हाथी का भाव पूछता है, क्योंकि दो पैसे का हाथी उसे महंगा लगता है। कुछ साल गुजरने के बाद यही दृश्य दोहराया जाता है और पिता फिर हाथी का भाव पूछता है तो उसे दो हजार रुपए बताया जाता है। पिता खुशी-खुशी बेटे के लिए हाथी खरीद लेता है। बेटा पिता से सवाल करता है कि दो पैसे का हाथी लेने से मना कर दिया था और आज दो हजार का हाथी आप ले रहे हैं। पिता ने एक पंक्ति में समझाया कि तब दो पैसे भी हमारे लिए दो हजार के समान थे। यही जीवन की रीत है और सुख और दुख चलता रहता है। ***सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार मलोट***

अनदेखी से बिगड़ती पारिस्थिति : विजय गर्ग

पर्यावरण को भारी नुकसान और जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया का ध्यान लगातार भविष्य की गंभीर चुनौतियों की ओर बना हुआ है। भारी विनाश के आसार नज़र आने के बावजूद, 'स्टैटिस्टिकल रिव्यू आफ वर्ल्ड एनर्जी' के एक ताजा अध्ययन में खुलासा हुआ है कि जीवाश्म ईंधनों की खपत और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। हालांकि अक्षय ऊर्जा स्रोतों में हुई वृद्धि के कारण वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में जीवाश्म ईंधनों की हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आई है। वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा की खपत अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 620 एक्साजूल पर पहुंच गई गई है। पहली बार कार्बन डाई आक्साइड का उत्सर्जन 40 गीगाटन के पार चला गया है। यह रपट विश्वमंच और पर्यावरण विश्लेषकों को यह समझने में मदद करती है कि निकट भविष्य की चुनौतियां कितनी भयावह हैं।

वैश्विक तापमान में एक में एक डिग्री का हर अंश प्राकृतिक प्रणालियों, मानव समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए के लिए महत्त्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम उत्पन्न सकता कर है। । वैश्विक तापमान वृद्धि को 1 सीमित करने के लिए 2022 के स्तर से 11.5 डिग्री सेल्सियस तक डाइआक्साइड उत्सर्जन में लगभग 37 गीगाटन की कटौती करने और 2050 तक ऊर्जा क्षेत्र में शुद्ध- शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की आवश्यकता है। कुछ प्रगति के बावजूद, ऊर्जा संक्रमण प्रौद्योगिकियों की वर्तमान तैनाती और इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों के 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित करने के पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्तरों के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर बना हुआ है। 1.5 डिग्री सेल्सियस के अनुकूल मार्ग मार्ग के लिए समाज द्वारा ऊर्जा के उपभोग और उत्पादन के तरीके व्यापक परिवर्तन की आव आवश्यकता है।

दीर्घकालिक निम्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन विकास रणनीतियां और शुद्ध-शून्य लक्ष्य, अगर पूरी तरह से क्रियान्वित किए जाते हैं, तो 2022 के स्तर की तुलना में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में छह फीसद और 2050 तक 56 फीसद की कमी आ सकती है। हालांकि, अधिकांश जलवायु प्रतिज्ञाओं को अभी विस्तृत राष्ट्रीय रणनीतियों और योजनाओं में तब्दील और क्रियान्वित किया जाना है, जिसके लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन चाहिए। नियोजित ऊर्जा परिदृश्य के अनुसार, ऊर्जा से संबंधित उत्सर्जन अंतर 2050 तक 34 गीगाटन तक पहुंचने का अनुमान है। डेढ़ डिग्री सेल्सियस पर बने रहने के लिए हर साल करीब एक हजार गीगावाट अक्षय ऊर्जा की जरूरत होती है। दो साल। दो साल पहले वैश्विक स्तर पर 300 गीगावाट अक्षय ऊर्जा जोड़ी गई, जो नई क्षमता का 83 फीसद है, जबकि जीवाश्म ईंधन और परमाणु ऊर्जा लिए संयुक्त हिस्सेदारी 17 फीसद है। अक्षय ऊर्जा की मात्रा और हिस्सेदारी दोनों में पर्याप्त वृद्धि की जरूरत है, है, जो तकनीकी रूप से संभव है।

करीब सन 2022 में रेकार्ड अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि हुई, इस वर्ष जीवाश्म ईंधन सबसिडी का उच्चतम स्तर भी देखा गया, क्योंकि कई सरकारों ने उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए उच्च ऊर्जा कीमतों के झटके को कम करने की कोशिश की। सभी ऊर्जा संक्रमण प्रौद्योगिकियों में वैश्विक निवेश 2022 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डालर के उच्च स्तर पर पहुंच गया, फिर भी जीवाश्म ईंधन में पूंजी निवेश अक्षय ऊर्जा निवेश से लगभग दोगुना था। जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा सामर्थ्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होने के कारण, सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवेश सही रास्ते पर हैं, अपने प्रयासों को दोगुना करने की आवश्यकता है।

ऊर्जा संक्रमण संकेतक ऊर्जा क्षेत्रों और प्रौद्योगिकियों में महत्त्वपूर्ण तेजी की आवश्यकता दर्शाते हैं। भविष्य में ये स्थितियां निवेश की जरूरतों और जलवायु परिवर्तन के बिगड़ते प्रभावों की लागत को भी बढ़ाएंगी। दूसरी ओर, अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद जीवाश्म ईंधनों की बढ़ती मांग भी गंभीर चिंता का विषय है। इससे पता चलता है कि स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग का मुकाबला दुनिया नहीं कर रही है। यानी ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने की दिशा में दुनिया को ऊर्जा उत्पादन में जिस बदलाव की जरूरत है, उसकी गति अब भी अपेक्षित नहीं है।

महा जानकार, जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल गिरावट न आने पर चिंता जताते हुए बताते हैं कि एक ऐसे वर्ष में, जहां हमने अक्षय ऊर्जा स्रोतों के योगदान को रेकार्ड स्तर बढ़ते देखा, दुनिया में ऊर्जा की मांग का स्तर भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा है। इसका मतलब है कि जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त ऊर्जा के हिस्से में कोई बदलाव नहीं आया है। भारत ऊर्जा मिश्रण में कोयले। की हिस्सेदारी करीब 55 फीसद है। भारत इसे अपने लिए सबसे अहम जीवाश्म ईंधन बताता है, क्योंकि देश में कोयले का बड़ा भंडार है। भारत ने सौर और पवन ऊर्जा में काफी विकास किया है, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में इनकी भागीदारी अब भी काफी कम है।

एक सच्चाई यह भी है कि दुनिया में जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल एक जैसा नहीं है। मसलन, यूरोप में जीवाश्म ईंधन की खपत का रुझान बदल रहा है। औद्योगिक क्रांति के से पहली बार यहां जीवाश्म ईंधनों से मिलने वाली ऊर्जा स्तर 70 फीसद से नीचे रहा है। इसकी एक वजह यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद रूसी गैस की खपत में आई कमी भी है। जर्मनी का कार्बन उत्सर्जन सात दशक में सबसे कम रहा है और कोयले की कम खपत ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। अमेरिका में भी कोयले के इस्तेमाल में 17 फीसद तक की गिरावट आई है। भारत में जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल बढ़ा है और इनकी कुल खपत में आठ फीसद की वृद्धि हुई। में ऊर्जा की बढ़ी मांग का तकरीबन पूरा हिस्सा जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा से पूरा हो रहा है।

चीन में एक ओर जहां सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में काफी काम हुआ, वहीं पिछले वर्ष तक यहां भी जीवाश्म ईंधनों का उपभोग छह फीसद बढ़ा है। हालांकि, अक्षय ऊर्जा स्रोतों चीन के बड़े निवेश में जानकार काफी संभावनाएं देखते हैं। पिछले वर्ष

वर्ष दुबई जलवायु सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय समुदाय पहली बार तेल, , गैस और कोयले से दूरी बनाने पर सहमत हुआ था। इस बात पर भी सहमति बनी कि सदस्य देशों को 2030 तक वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने और उसी अवधि के भीतर ऊर्जा दक्षता की दर को दोगुना करने का प्रयास करना चाहिए। 2050 तक, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक कम किया जाना चाहिए। इस प्रकार जीवाश्म ईंधन युग के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया और मान्यता दी कि नवीकरणीय ऊर्जा जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय के लिए वैश्विक समाधान है। सवाल है कि उस जलवायु सम्मेलन के निर्णयों की दिशा में अब तक कैसी पहल हो सकी है। बदलती जलवायु, धूसर पर्यावरण, मानसूनी विचलनों के बीच इस बार की गर्मी ने कहर बरपा दिए। तब भी आंखें खुल जाएं तो गनीमत है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार मलोट पंजाब

भारत कैसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के परिदृश्य को पुनर्परिभाषित कर रहा है

विजय गर्ग

भारत कई पहलों और विकासों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। यहां कुछ प्रमुख तरीके दिए गए हैं जिनसे यह परिवर्तन हो रहा है: 2025 तक, 2 मिलियन से अधिक भारतीय छात्रों के विदेशों में अध्ययन करने की उम्मीद है, जिससे भारत विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन जाएगा। यह प्रवृत्ति विदेश में विदेशी कॉलेजों में पढ़ने की उम्मीद रखने वाले भारतीय छात्रों तक ही सीमित नहीं है; इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के विदेशी परिसरों में अध्ययन करना चाहते हैं। एक ओर, दशकों के इतिहास वाले विरासत इंजीनियरिंग और मेडिकल स्कूल अंतरराष्ट्रीय शाखाएं स्थापित कर रहे हैं। दूसरी ओर, हम नए जमाने के बिजनेस और मैनेजमेंट स्कूलों को दुबई, लंदन, सिंगापुर और सिडनी जैसे प्रमुख वैश्विक बिजनेस केंद्रों में पैर जमाते हुए देख रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन हासिल करने के लिए क्रांतिकारी नए तरीके पेश कर रहे हैं। कई प्रमुख कारकों ने इस विस्तार को प्रेरित किया है। 1. विश्वसनीय ब्रांड भारतीय छात्र तेजी से उन ब्रांडों के साथ विदेश में अध्ययन करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं जिन्हें वे जानते हैं और जिन पर वे भरोसा करते हैं। विदेशों में कैंपस स्थापित करके, भारतीय संस्थान अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन हासिल करने और एक विश्वसनीय भारतीय शैक्षिक प्रणाली के दायरे में रहते हुए विदेश में रहने के लाभों का अनुभव करने का सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं। यह पहली बार विदेश जाने वाले युवा छात्रों के लिए संक्रमण को आसान बनाता है, एक सहायता प्रणाली प्रदान करता है जो उनकी सांस्कृतिक और शैक्षिक आवश्यकताओं को समझता है। 2. भारतीय प्रतिभा को उजागर करना और वैश्विक कौशल अंतराल को पाटना भारतीय शिक्षा, विशेष रूप से एसटीईएम और प्रबंधन क्षेत्रों में, अत्यधिक कुशल स्नातक तैयार करने के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया की कुछ अग्रणी प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक कंपनियों के नेताओं पर विचार करें।

Google, Microsoft, IBM, Adobe और कई अन्य कंपनियों में भारतीय या भारतीय मूल के सीईओ हैं। इन वैश्विक शक्तियों का नेतृत्व करने वाले भारतीय सीईओ की सफलता दुनिया भर में भारतीय शैली की शिक्षा की जबरदस्त मांग को रेखांकित करती है। विदेशों में कैंपस स्थापित करके, भारतीय संस्थान भविष्य के वैश्विक व्यापार और प्रौद्योगिकी नेताओं को तैयार करने के लिए इस सफलता का लाभ उठा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उसी शैक्षिक उत्कृष्टता का लाभ उठाने का सुनहरा अवसर मिलता है जिसने आज के तकनीकी और व्यावसायिक परिदृश्य में कुछ प्रतिभाशाली दिमागों को आकार दिया है। 3. भारतीय मान्यता के साथ वैश्विक अनुभव भारत लौटने की योजना बना रहे छात्रों के लिए, भारतीय संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय परिसरों द्वारा दी जाने वाली डिग्रियाँ भारतीय नौकरी बाजार में महत्वपूर्ण मूल्य रखती हैं। छात्र अमूल्य अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करते हुए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त डिग्री प्राप्त करते हैं। नियोक्ता इन स्नातकों के अद्वितीय कौशल सेट, वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ भारतीय शैक्षिक मानकों में एक ठोस आधार की सराहना करते हैं। इससे उनकी अत्यधिक मांग रहती है, विशेषकर बहुराष्ट्रीय निगमों और वैश्विक दृष्टिकोण वाले उद्योगों में। 4. कैरियर के परिणामों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करें व्यापक-आधारित शिक्षा पर जोर देने वाले कई पश्चिमी विश्वविद्यालयों के विपरीत, भारतीय स्कूल रोजगार पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। यह नौकरी-केंद्रित दृष्टिकोण भारतीय उच्च शिक्षा के डीएनए में गहराई से अंतर्निहित है, जो देश के प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार और इसकी युवा आबादी की आकांक्षाओं को दर्शाता है। जैसे-जैसे भारतीय विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर विस्तार कर रहे हैं, वे इस कैरियर-उन्मुख मॉडल का निर्यात कर रहे हैं। चाहे वह एक विशेष एमबीए कार्यक्रम हो या तकनीक-केंद्रित पाठ्यक्रम, भारतीय संस्थान उद्योग की जरूरतों और नौकरी पर स्पष्ट नजर रखते हुए अपनी पेशकश तैयार करते हैं। बाजार के रुझान। यह केंद्रित दृष्टिकोण ऐसे युग में विशेष रूप से आकर्षक है जहां छात्र और अभिभावक शिक्षा में निवेश पर रिटर्न के बारे में चिंतित हैं। 5. सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं विविधता अंतर्राष्ट्रीय परिसर सांस्कृतिक आदान-प्रदान के केंद्र हैं। भारतीय छात्रों को विविध पृष्ठभूमि के साथियों के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है, जिससे उन्हें अमूल्य अनुभव प्राप्त होता है जो उन्हें अन्यथा घर पर नहीं मिलता। वे बहुसांस्कृतिक टीमों में काम करना सीखते हैं और ऐसे कौशल विकसित करते हैं जो उन्हें अपने घरेलू साथियों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देते हैं। इसके विपरीत, अंतर्राष्ट्रीय छात्र भारतीय संस्कृति और व्यावसायिक प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, जो भारत के वैश्विक आर्थिक प्रभाव बढ़ने के साथ-साथ अधिक मूल्यवान है। यह सांस्कृतिक विसर्जन कक्षा से आगे तक जाता है। छात्र अंतर-सांस्कृतिक गतिविधियों, समारोहों और परियोजनाओं में संलग्न होते हैं, जिससे विभिन्न विश्वदृष्टिकोणों की गहरी समझ और सराहना को बढ़ावा मिलता है। यह अनुभव वैश्विक नागरिकों को विकसित करने में अमूल्य है जो सहानुभूति और सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता के साथ परस्पर जुड़ी दुनिया की जटिलताओं से निपट सकते हैं। 6. अनुसंधान सहयोग और नवाचार विदेशी परिसर भारतीय संस्थानों को वैश्विक अनुसंधान संसाधनों का लाभ उठाने, नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर ज्ञान की उन्नति में योगदान करने में सक्षम बनाते हैं। ये सहयोग अक्सर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने वाली अभूतपूर्व अनुसंधान पहलों को जन्म देते हैं। भारतीय अनुसंधान पद्धतियों की ताकत को अंतरराष्ट्रीय संसाधनों और दृष्टिकोणों के साथ जोड़कर, ये संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, इन सहयोगों के परिणामस्वरूप अक्सर संयुक्त अनुसंधान प्रकाशन, पेटेंट और नवाचार होते हैं जो भारतीय शिक्षा जगत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। वे भारत और विदेश दोनों में शैक्षणिक वातावरण को समृद्ध करते हुए संकाय विनिमय कार्यक्रमों के अवसर भी प्रदान करते हैं। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय शैक्षणिक संस्थानों का वैश्विक विस्तार सिर्फ एक प्रवृत्ति से कहीं अधिक है; यह भारतीय शिक्षा की उत्कृष्टता और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। यह हमारी मूल शक्तियों को बनाए रखते हुए वैश्विक शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने की हमारी क्षमता को रेखांकित करता है। फिर भी, यह यात्रा बाधाओं से रहित नहीं है। विभिन्न नियामक परिवेशों को अपनाना, सीमाओं के पार लगातार गुणवत्ता सुनिश्चित करना और भारतीय मूल्यों के साथ स्थानीय प्रासंगिकता को संतुलित करना निरंतर चुनौतियाँ हैं। इनके लिए निरंतर नवाचार और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। इन चुनौतियों के बावजूद भविष्य उज्ज्वल है। जैसे-जैसे भारतीय संस्थान अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करना जारी रखते हैं, वे न केवल अपना कद बढ़ाते हैं बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर और वैश्विक प्रभाव में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

विदेशी कर्ज के मौजूदा बोझ से चिंतित नहीं सरकार, 2026 से जीडीपी-उधारी अनुपात घटाने पर होगा फोकस

विपक्षी दल लगातार आलोचना कर रहे हैं कि कुल व्यय में 19 फीसद हिस्सा उधारी का ब्याज चुकाया जा रहा है। लेकिन वित्त मंत्रालय के अधिकारी तेज गति से बढ़ने वाले भारत के लिए इसे चिंता का विषय नहीं माना है। उनका कहना है कि भारत ना सिर्फ तेज विकास दर वाला देश है बल्कि इसका विदेशी मुद्रा भंडार भी काफी विशाल है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। आम बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि इस वर्ष 14.01 लाख करोड़ रुपये की उधारी लेगी, जो वर्ष 2023-24 के मुकाबले 12 हजार करोड़ रुपये कम होगा। बजट के एक दिन बाद वित्त मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने विदेशी व घरेलू उधारी को लेकर सरकार की दीर्घकालिक रणनीति के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि उधारी को सिर्फ राजकोषीय घाटे के साथ जोड़ कर देखा जाना चाहिए। सरकार का उद्देश्य वर्ष 2026 के बाद ना सिर्फ राजकोषीय घाटे को 4.5 फीसद से नीचे लाने का होगा बल्कि जीडीपी के मुकाबले उधारी का अनुपात भी कम करने का होगा।

विदेशी कर्ज चिंता की बात नहीं

विपक्षी दलों की ओर से आलोचना की जा रही है कि कुल व्यय में 19 फीसद हिस्सा उधारी का ब्याज चुकाया जा रहा है। जबकि वित्त मंत्रालय के अधिकारी तेज गति से बढ़ने वाले भारत के लिए इसे चिंता का विषय नहीं माना है।

वित्त सचिव टी वी स्वामीनाथन के मुताबिक, "वर्ष 2026-27 के बाद से हम जीडीपी के मुकाबले उधारी के स्तर को लगातार नीचे लाने पर ज्यादा फोकस करेंगे। जहां तक विदेशी कर्ज की बात है तो भारत जैसे तेज विकास दर वाली बड़ी इकोनमी में इसका महत्व सुस्त विकास दर वाले देशों के मुकाबले अलग होता है। भारत ना सिर्फ तेज विकास दर वाला देश है बल्कि इसका विशाल विदेशी मुद्रा भंडार (661 अरब डॉलर), दुनिया के दूसरे देशों की मुद्राओं के मुकाबले स्थिर करेंसी भी और लगातार बढ़ता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तीन अन्य कारण है जो विदेशी कर्ज के खतरे को कम करता है।"

लगातार घट रहा भारत का कर्ज

अगर दो दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण में भारत पर विदेशी कर्ज की राशि का आकलन करें तो यह बात साफ नजर आती है कि सरकार विदेशी कर्ज के स्तर को एक निश्चित सीमा के बीच स्थिर रखने में सफल रही है। इसमें लगातार कमी भी हो रही है। मार्च, 2023 में जीडीपी व विदेशी कर्ज का अनुपात 19 फीसद था जो मार्च, 2024 में घट कर 18.7 फीसद पर आ गया है। इस दौरान एक वर्ष के भीतर चुकाये जाने वाले विदेशी कर्ज का हिस्सा कुल विदेशी कर्ज में 20.6 फीसद से घट कर 18.5 फीसद पर आ गया है। वर्ष 2021 में देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 100.6 फीसद विदेशी कर्ज था जो आज की तारीख में घट कर 99.7 फीसद हो गया है।

सनद रहे कि दिसंबर, 2023 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत पर कुल उधारी का स्तर इसके जीडीपी के बराबर (100 फीसद से ज्यादा) होने की तरफ अग्रसर है। इसने जो आंकड़ा दिया था उसके मुताबिक वर्ष 2021-22 में देश के जीडीपी के अनुपात में कुल उधारी 83.8 फीसद था। इसमें घरेलू कर्ज का अनुपात 59.5 और विदेशी कर्ज का अनुपात 19.7 फीसद था। अब इस आंकड़े में सुधार दिख रहा है। जीडीपी के अनुपात में कुल कर्ज का स्तर घट कर 82 फीसद पर आ गया है। वित्त मंत्रालय मान रहे हैं कि इसमें आने वाले वर्षों में और तेज गति से गिरावट होगी।

समय से पहले उधारी चुकाएगी सरकार

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से जब यह पूछा गया कि क्या कुल व्यय में ब्याज भुगतान का हिस्सा भी मौजूदा 19 फीसद से कम होगा तो उनका जवाब था कि सरकार की योजना लगातार 7-8 फीसद की विकास दर हासिल करने की है। हमारा आकलन है कि राजस्व संग्रह भी तेजी से बढ़ेगा और व्यय भी तेज होगा।

उन्होंने कहा कि अगर राजकोषीय संतुलन पर सरकार अपनी योजना के मुताबिक आगे बढ़ती है तो समय से पहले भी उधारी चुकाने पर विचार किया जा सकता है। ऐसा पहले भी किया गया है। लेकिन तेज विकास दर के लिए हमें लगातार नई उधारी भी लेने की जरूरत होगी क्योंकि हमें विश्वस्तरीय ढांचागत सुविधाओं को लगाना होगा, समाजिक विकास की गुणवत्ता को बेहतर करना है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि ब्याज अदाएगी में बोझ को कम किया जा सकता है या नहीं।

आय नहीं, निवेश पर लगता था एंजल टैक्स; क्या इसे हटाने से विदेशी निवेश लाने में मिलेगी मदद?

अगर कोई स्टार्टअप विदेश से कोई निवेश हासिल करता है तो उस निवेश को अन्य माध्यम से आय मानते हुए उस पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगता था जिसे एंजल टैक्स कहा जाता था। अपनी फेयर वैल्यू से जितनी अधिक राशि स्टार्टअप किसी एंजल निवेशक से जुटाता था उस पर एंजल टैक्स वसूला जाता था। लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है।

नई दिल्ली। स्टार्टअप से एंजल टैक्स हटाने का मुद्दा लंबे समय से लंबित था और चूंकि यह कर देश में आने वाले निवेश पर लगाया जाता था और इस तरह के विदेशी निवेश पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। यह बात उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कही है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से विदेशी निवेश आकर्षित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

विवाद और मुकदमेबाजी में आएगी कमी

सिंह ने बताया, 'एंजल टैक्स का मुद्दा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ कर का भी मुद्दा था। दरअसल, यह आय पर नहीं बल्कि निवेश पर कर था और निवेश पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए और यही मूल विचार है।" सिंह ने कहा कि इस फैसले से विवाद और मुकदमेबाजी भी कम होगी। निवेशक नए नवाचार पर निवेश करता है और यह कर उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है।

उन्होंने कहा, "वास्तव में यह भारत में एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) को कम करता है।" ऐसे निवेश से जुड़े मनी लॉन्डिंग संबंधी मुद्दों के बारे में अधिकारियों की चिंता पर सिंह ने कहा, 'इसके लिए पहले से कानून मौजूद है। आप एक, दो या तीन प्रतिशत लोगों से निपटने के लिए ऐसे 97 प्रतिशत लोगों पर बोझ डाल रहे हैं जो वास्तव में नवोन्मेषी है और एक विचार को मूर्तरूप देने के लिए निवेश प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।"

क्या था एंजल टैक्स का नियम

अगर कोई स्टार्टअप विदेश से कोई निवेश हासिल करता है तो उस निवेश को अन्य माध्यम से आय मानते हुए उस पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगता था, जिसे एंजल टैक्स कहा जाता था। अपनी फेयर वैल्यू से जितनी अधिक राशि स्टार्टअप किसी एंजल निवेशक से जुटाता है, उस पर एंजल टैक्स वसूला जाता था।

जैसे कि किसी स्टार्टअप की फेयर वैल्यू एक करोड़ है और वह 1.5 करोड़ रुपये एंजल निवेशकों से जुटाता है तो 50 लाख रुपये पर एंजल टैक्स लगता था। लेकिन, अब इसे खत्म कर दिया गया है।

IFCI के शेयरों में लगा 20 फीसदी का अपर सर्किट, एक साल में मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है सरकारी कंपनी

IFCI एक सरकारी NBFC है। इसकी नींव 1948 में रखी गई थी खासतौर पर औद्योगिक परियोजनाओं को लंबी अवधि की वित्तीय सहायता देने के लिए। बुधवार (24 जुलाई) को भी IFCI के स्टॉक्स 20 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 83 .95 रुपये के स्तर पर बंद हुए। आइए जानते हैं कि यह कंपनी क्या कारोबार करती है और इसके शेयरों में तेजी की वजह क्या है?

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार अभी बजट में कैपिटल गेन पर बढ़े टैक्स के झटके से नहीं उबरा है। सेसेंक्स और निफ्टी लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। पूरे दिन के कारोबार में भारी-उतार लगा रहा। एक वक्त तो सेंसेक्स करीब 700 अंकों तक लुढ़क गया था।

लेकिन, इस गिरावट के बावजूद कुछ कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी दिखी। इनमें से एक है, सरकारी क्षेत्र की IFCI। बुधवार (24 जुलाई) को भी IFCI के स्टॉक्स 20 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 83.95 रुपये के स्तर पर बंद हुए। आइए जानते हैं कि यह कंपनी क्या कारोबार करती है और इसके शेयरों में तेजी की वजह क्या है?

क्या करती है IFCI?

IFCI एक सरकारी NBFC है। इसकी नींव 1948 में रखी गई थी, खासतौर पर औद्योगिक परियोजनाओं को लंबी अवधि की वित्तीय सहायता देने के लिए। इसे पहले इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी कहा जाता था। IFCI अब एयरपोर्ट, सड़क, दूरसंचार, बिजली, रियल एस्टेट, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े प्रोजेक्ट को कर्ज उपलब्ध कराती है। सरकार भी इन क्षेत्रों पर फोकस बढ़ा रही है, जिसकी वजह से निवेशक IFCI पर बड़ा दांव लगा रहे हैं।

कितना मिला रिटर्न?

IFCI के शेयर ने पिछले एक महीने में निवेशकों को करीब 38 फीसदी का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने की बात करें, तो निवेशकों को 75 फीसदी का मुनाफा हुआ है। एक साल में तो IFCI ने 558.43 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इस स्टॉक में भी बजट के दिन गिरावट आई थी, लेकिन यह उस झटके से काफी तेजी से उबर गई है।

IFCI का वित्तीय प्रदर्शन

IFCI का वित्त वर्ष 2023-24 में एक तरह से कायाकल्प हुआ। इसकी शुद्ध बिक्री एक साल पहले के मुकाबले 17.2 प्रतिशत बढ़कर 1,986.58 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी को 241.05 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। इससे पहले कंपनी लगातार पांच साल से घाटा दर्ज कर रही थी। इससे कंपनी की वित्तीय सेहत में सुधार का बड़ा संकेत मिलता है।

हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय वेटिंग पीरियड को देखना क्यों है जरूरी?

हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए तब सबसे अहम साबित होता है जब हम किसी मेडिकल इमरजेंसी का सामना करने हैं। ऐसे में हर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। मगर हेल्थ इंश्योरेस में एक वेटिंग पीरियड होता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको यहां इससे जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस हमारे एक अहम जरूरत में गिने जाते हैं। ये खासकर तब सबसे ज्यादा काम आते हैं, जब आपके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है या किसी मेडिकल इमरजेंसी के चलते बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं।

वैसे तो हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हम हर चीज को बहुत ध्यान से चेक करते हैं, लेकिन एक अहम चीज है जो हमारे दिमाग में नहीं आती है। पॉलिसी लेते समय हम वेटिंग पीरियड को अनदेखा कर देते हैं। यह समय कुछ दिनों से लेकर कई सालों तक हो सकता है। यह पीरियड ये निर्धारित करता है कि आप खास स्थितियों में अपने इश्योरेंस को कब क्लेम कर सकते हैं। ये अवधि हर स्थिति के हिसाब से अलग हो सकती है।आइये इसके बाके में जानते हैं।

क्या होता है वेटिंग पीरियड?

● वेटिंग पीरियड आपके पॉलिसी खरीदने की शुरुआत और क्लेम करने तक के बीच का समय होती हैं।

● यह समयसीमा बीमा कंपनियों द्वारा जोखिमों को कम करने के लिए लगाई जाती है।

● आपको बता दें कि ये वेटिंग पीरियड कई प्रकार के होते हैं। यहां हम इनके बारे में जानेंगे।

स्टैंडर्ड कूलिंग-ऑफ पीरियड

● ये वेटिंग पीरियड 30-दिनों का होता है। ये किसी भी पॉलिसी का बेसिक वेटिंग पीरियड होता है।

● अगर इस बीच आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आप इसे क्लेम नहीं कर सकते हैं।

● हालांकि अगर आप किसी दुर्घटना की स्थिति में आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं।

मौजूदा बिमारी के लिए वेटिंग पीरियड

● अब सवाल उठता है कि अगर आपको पहले से ही कोई बिमारी हो तो उस स्थिति में वेटिंग पीरियड कैसे काम करता है।

● ऐसे स्थिति को कवर किए जाने से पहले आमतौर पर दो से चार साल के बीच का वेटिंग पीरियड होता है।

● ऐसे में अगर इस अवधि के दौरान आपको उस बिमारी से कोई समस्या होती है तो आपको कोई कवर नहीं मिलता है।

किसी खास बिमारी के लिए वेटिंग पीरियड

● अगर पॉलिसीधारक हर्निया, मोतियाबिंद, जोड़ रिप्लेसमेंट और कैंसर सर्जरी जैसी बड़ी बीमारियों से प्रभावित है तो ऐसे में अक्सर दो से चार साल तक का वेटिंग पीरियड होता है।

● इसके बारे में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आपको पहले ही बता दिया जाता है।

मैट रनिटी वेटिंग पीरियड

● आम तौर पर कंपनियां मैटरनिटी को हेल्थ पॉलिसी से बाहर ही रखती है। मैटरनिटी कवरेज के लिए आपको नौ महीने से तीन साल के बीच का वेटिंग पीरियड सेट किया गया है।

मानसिक बीमारियों का वेटिंग पीरियड

● हेल्थ कंपनिया का मानसिक बीमारियों के लिए कवरेज अक्सर दो साल तक के वेटिंग पीरियड के साथ आता है।

कैसे कम करें वेटिंग पीरियड

● हर कंपनी अलग-अलग वेटिंग पीरियड ऑफर करती है, ऐसे में जो कंपनी कम वेटिंग पीरियड दे रही है, उसकी पॉलिसी चुनें। की प्रतीक्षा अवधि अलग-अलग होती है।

● पहले से मौजूद बीमारियों के लिए, टॉप-अप प्लान सबसे बेहतर और फायदेमंद हो सकते है। ये प्लान एक सीमा से ऊपर एक्स्ट्रा कवरेज देते हैं।

● आप हाई प्रीमियम का भुगतान करके खास स्थिति में वेटिंग पीरियड को कम करने की अनुमति पा सकते हैं।

कुकिंग ऑयल पर आयात शुल्क न बढ़ाने से इंडस्ट्री निराश, घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मांगा फंड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में कहा था कि दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए हम इनके उत्पादन भंडारण और विपणन को मजबूत करेंगे। खाद्य तेल उद्योग संगठन SEA का कहना है कि सरकार को तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना चाहिए।

नई दिल्ली। खाद्य तेल उद्योग संगठन साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एसईए) ने बजट में कुकिंग ऑयल तेल पर आयात शुल्क न बढ़ाए जाने पर निराशा जताई है। उद्योग संगठन का कहना है कि सरकार को तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना चाहिए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में कहा था कि दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए हम इनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेंगे। बजट प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया देते हुए एसईए के प्रेसिडेंट अजय झुनझुनवाला ने कहा कि हम खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन को लेकर सरकार को बधाई देते हैं।

उन्होंने कहा, 'इस मिशन में सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हमें विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण मिशन को पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा, जिससे आने वाले वर्षों में आयात पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण परिणाम सुनिश्चित होंगे।'

वित्त मंत्री ने बजट में क्या कहा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, 'हम तिलहन के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेंगे। इस पहल का मकसद सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों में 'आत्मनिर्भरता' हासिल करना है। हमने अंतरिम बजट के एलान के मुताबिक सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने की रणनीति बनाई गई है।'

कमजोर मांग और आयात शुल्क में कटौती के असर, सोने के दाम में गिरावट जारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट भाषण में सोने पर कस्टम ड्यूटी घटाने का एलान किया था। इसके बाद से सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। मंगलवार को सोना 3350 रुपये सस्ता होकर 72300 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। बुधवार को भी सोने के भाव में 650 रुपये की गिरावट आई है।

नई दिल्ली। आभूषण विक्रेताओं की कमजोर मांग और 2024-25 के बजट में आयात शुल्क में कटौती की घोषणा के कारण बुधवार को सोने का भाव 650 रुपये घटकर 71,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, मंगलवार को पिछले सत्र में यह कीमती धातु 3,350 रुपये की गिरावट के बाद 72,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी की कीमत 87,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही।

99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 650-650 रुपये घटकर क्रमशः 71,650 रुपये प्रति 10 ग्राम और 71,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। व्यापारियों ने सोने की कीमतों में गिरावट का श्रेय सरकार द्वारा सोने और चांदी सहित कई उत्पादों पर सीमा शुल्क में कटौती के कदम को दिया। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया। पिछले दो सत्रों में सोने की कीमतों में 4000 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है।

बजट में घटा आयात शुल्क

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में कमोडिटी रिसर्च के वरिष्ठ विश्लेषक मानव मोदी ने कहा, ₹वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भारत के वित्त मंत्री ने आयात शुल्क में कटौती की घोषणा की। इसका सोने-चांदी के बाजार पर असर दिखा। दूसरी ओर, कॉमेक्स पर कीमतों में तेजी आई, जिससे घरेलू कीमतों के साथ इसकी असमानता बढ़ गई।₹

मोदी का कहना है कि शुल्क कटौती के प्रभाव और कॉमेक्स के साथ तालमेल लाने में घरेलू कीमतों को भी कुछ समय लग सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, कॉमेक्स सोना 6 डॉलर प्रति औंस की बढ़त के साथ 2,461.20 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

अमेरिकी डेटा पर नजरें

कोटक सिक्योरिटीज की कमोडिटी रिसर्च की एवीपी कायनात चैनवाला ने कहा, ₹बुधवार को सोने में बढ़त जारी रही और यह 2410 डॉलर प्रति औंस से ऊपर कारोबार कर रहा है। यह अमेरिका में आगामी डेटा रिलीज की उम्मीद के बीच संभव है, जो फेड की दरों में कटौती का समर्थन कर सकता है।₹

जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज में ईबीजी-कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च के उपाध्यक्ष प्रणव मेर के अनुसार, मंगलवार को ड्यूटी कट के कारण हुई तेज बिकवाली के बाद विदेशी बाजार में बढ़त और सुधारात्मक स्तरों पर खरीदारी के समर्थन के चलते सोने की कीमतें सकारात्मक रूप से कारोबार कर रही हैं।

मेर ने कहा कि आगे चलकर, व्यापारियों का ध्यान गुरुवार को आने वाले अमेरिकी जीडीपी डेटा और शुक्रवार को आने वाले व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मुद्रास्फीति डेटा पर रहेगा, जो फेड की दरों में कटौती के बारे में अधिक संकेत दे सकता है।

भगवान शिव के कुछ रहस्य

आदिनाथ शिव-:

सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार-प्रसार का प्रयास किया इसलिए उन्हें 'आदिदेव' भी कहा जाता है। 'आदि' का अर्थ प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम 'आदिश' भी है।

शिव के अस्त्र-शस्त्र-:

शिव का धनुष पिनाक, चक्र भवरेंदु और सुदर्शन, अस्त्र पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था।

भगवान शिव का नाग-:

शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकि है। वासुकि के बड़े भाई का नाम शेषनाग है।

शिव की अर्द्धांगिनी-:

शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा, उर्मि, काली कही गई हैं।

शिव के पुत्र-:

शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं- गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक है।

शिव के शिष्य-:

शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया जिसके चलते भिन्न-भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं- बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेन्द्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज इसके अलावा 8वें गौरशिरस मुनि भी थे।

शिव के गण-:

शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख हैं। इसके अलावा, पिशाच, दैत्य और नाग-नागिन, पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है।

शिव पंचायत-:

भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहलाते हैं।

शिव के द्वारपाल-:

नंदी, स्कंद, रिटी, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा-महेश्वर और महाकाल।

शिव पार्षद-:

जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद हैं।

सभी धर्मों का केंद्र शिव-:

शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजीदी, साबिईन, सुबी, इब्राहीमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई।

बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ अंतरराष्ट्रीय-:

ख्यातिप्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पालि ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अतिप्राचीन हैं- तणंकर, शणंकर और मेघंकर।

देवता और असुर दोनों के प्रिय शिव-:

भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव, सभी आदिवासी, वनवासी जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं।

शिव चिह्न-:

वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिह्न की पूजा कर सकें, उस पत्थर के ढेले, बटिया को शिव का चिह्न माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिह्न माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्द्ध चन्द्र को भी शिव का चिह्न मानते हैं, हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं।

शिव की गुफा-:

शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकूटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था वह गुफा 'अमरनाथ गुफा' के नाम से प्रसिद्ध है।

शिव के पैरों के निशान-:

श्रीपद- श्रीलंका में रतन द्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान हैं। ये पदचिह्न 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को सिवानोलीपदम कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक कहते हैं।

रुद्र पद- तमिलनाडु के नागपट्टीनम जिले के थिरुवेंगडू क्षेत्र में श्रीस्वेदारण्येश्वर का मंदिर में शिव के पदचिह्न हैं जिसे 'रुद्र पदम' कहा जाता है। इसके अलावा थिरुवन्नामलाई में भी एक स्थान पर शिव के पदचिह्न हैं।

तेजपुर- असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान है।

जागेश्वर- उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी से लगभग साढ़े 4 किलोमीटर दूर जंगल में भीम के पास शिव के पदचिह्न हैं। पांडवों को दर्शन देने से बचने के लिए उन्होंने अपना एक पैर यहां और दूसरा कैलाश में रखा था।

रांची- झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर 'रांची हिल' पर शिवजी के पैरों के निशान हैं। इस स्थान को 'पहाड़ी बाबा मंदिर' कहा जाता है।

शिव के अवतार-:

वीरभद्र, पिप्पलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, शरभावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्णदर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुनटनर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यानाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, द्विज, नतेश्वर आदि हुए हैं। वेदों में रुद्रों का जिक्र है। रुद्र 11 बताए जाते हैं- कपाली, पिंगल, भीम, विरुपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुध्य, शंभू, चण्ड तथा भव।

शिव का विरोधाभासिक परिवार-:

शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकि नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन हैं। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषकभक्षी जीव है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिवजी का वाहन तो नंदी बैल है। इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार में एकता है।

शिव निवास-:

तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है। जहां पर शिव विराजमान हैं उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्माजी का स्थान है।

शिव भक्त-:

ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी- देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिव भक्त है। हरिवंश पुराण के अनुसार, कैलास पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा-अर्चना की थी।

शिव ध्यान-:

शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान-पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बिल्वपत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है।

शिव मंत्र-:

दो ही शिव के मंत्र हैं पहला- ॥ॐ नमः शिवाय॥। दूसरा महामृत्युंजय मंत्र- ॐ ह्रौं जू सः। ॐ भूः भुवः स्वः। ॥ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्। स्वः भुवः भूः ॐ। सः जू ह्रौं ॐ ॥ है।

शिव व्रत और त्योहार-:

सोमवार, प्रदोष और श्रावण मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख पर्व त्योहार है।

शिव प्रचारक-:

भगवान शंकर की परंपरा को उनके शिष्यों बृहस्पति, विशालाक्ष (शिव), शुक्र, सहस्राक्ष, महेन्द्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज, अगस्त्य मुनि, गौरशिरस मुनि, नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया। इसके अलावा वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, बाण, रावण, जय और विजय ने भी शैवपंथ का प्रचार किया। इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम आदिगुरु भगवान दत्तात्रेय का आता है। दत्तात्रेय के बाद आदि शंकराचार्य, मत्स्येन्द्रनाथ और गुरु गुरुगोरखनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।

शिव महिमा-:

शिव ने कालकूट नामक विष पिया था जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का पांचवां सिर काट दिया था।

शैव परम्परा-:

दसनामी, शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, कश्मीरी शैव, वीरशैव, नाग, लकुलीश, पाशुपत, कापालिक, कालदमन और महेश्वर सभी शैव परंपरा से हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही माने जाते हैं। भारत की असुर, रक्ष और आदिवासी जाति के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है।

शिव के प्रमुख नाम-:

शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं जिनमें 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है लेकिन यहां प्रचलित नाम जानें- महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्रियंबक, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलयंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिवशंभु, भूतनाथ और रुद्र।

अमरनाथ के अमृत वचन-:

शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया उस ज्ञान की आज अनेकानेक शाखाएं हो चली हैं। वह ज्ञानयोग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। 'विज्ञान भैरव तंत्र' एक ऐसा ग्रंथ है, जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है।

शिव ग्रंथ-:

वेद और उपनिषद सहित विज्ञान भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है।

शिवलिंग-:

वायु पुराण के अनुसार प्रलयकाल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टिकाल में जिससे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु-नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि। यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा-अर्चना है।

बारह ज्योतिर्लिंग-:

सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ॐकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथजी, त्र्यम्बकेश्वर, केदारनाथ, घृष्णेश्वर। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में अनेकों मान्यताएं प्रचलित है। ज्योतिर्लिंग यानी 'व्यापक ब्रह्मात्मलिंग' जिसका अर्थ है 'व्यापक प्रकाश'। जो शिवलिंग के बारह खंड हैं। शिवपुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योति पिंड कहा गया है।

दूसरी मान्यता अनुसार शिव पुराण के अनुसार प्राचीनकाल में आकाश से ज्योति पिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेकों उल्का पिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। भारत में गिरे अनेकों पिंडों में से प्रमुख बारह पिंड को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया।

शिव का दर्शन-:

शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिवभक्त हैं, क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपनी चित्तवृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। आइंस्टीन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

शिव और शंकर-:

शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं- शिव, शंकर, भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में, दोनों की प्रतिमाएं अलग-अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अतः शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं है। हालांकि शंकर को भी शिवरूप माना गया है। माना जाता है कि महेष (नंदी) और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं।

देवों के देव महादेव-:

देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए इसीलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी।

शिव हर काल में-:

भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। राम के समय भी शिव थे। महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए।

बजट 2024: सरकार ने दिखाया विकास का लक्ष्य, बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर हमलावर रहा विपक्ष; भाजपा ने भी किया पलटवार

लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान पूरा विपक्षी खेमा सरकरा पर हमलावर रहा। विपक्ष की ओर से बजट पर चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस सदस्य कुमारी शैलजा ने तीखा प्रहार किया। कांग्रेस के शशि थरूर ने सरकार पर योजनाओं के नाम बदलने को लेकर तंज कसा कि आयुष्मान वेलनेस सेंटर का नाम अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है।

नई दिल्ली। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान पूरा विपक्षी खेमा लगभग समान लकीर पर चला। एनडीए सरकार को घेरने के लिए आरोप तो कई लगाए, लेकिन सबसे अधिक जोर इसी आरोप पर रहा कि इस बजट के माध्यम से सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देकर अपने गठबंधन सहयोगियों को साधने का प्रयास किया है। हालांकि, सरकार की ओर से भी उसी धार के साथ पलटवार किया गया।

कांग्रेस ने केंद्र पर किया तीखा प्रहार

सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां गिनाते हुए विकास का दूरदर्शी लक्ष्य दिखाया और दावा किया कि 400 सीटें भी पार करेंगे और 2047 तक राजग की सरकार भी रहेगी। विपक्ष की ओर से बजट पर चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस सदस्य कुमारी शैलजा ने तीखा प्रहार किया।

यह कुर्सी बचाओ बजट है: कुमारी शैलजा

उन्होंने बजट में तमाम खामियां गिनाते हुए तंज कसा कि यह कुर्सी बचाओ बजट है। उनका इशारा बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज दिए जाने को लेकर था। साथ ही प्रश्न भी खड़े किए कि हरियाणा को कुछ क्यों नहीं दिया गया? आरोपों की इसी धार को विपक्षी खेमे के अन्य नेताओं ने भी आगे बढ़ाया।

शशि थरूर ने योजनाओं के नाम बदलने को लेकर कसा तंज

कांग्रेस के शशि थरूर ने सरकार पर योजनाओं के नाम बदलने को लेकर तंज कसा कि आयुष्मान वेलनेस सेंटर का नाम अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। भाजपा को उत्तर प्रदेश से सबक ले लेना चाहिए कि मंदिर का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं करे।

भाजपा सांसदों ने विपक्ष को दिया जवाब

वहीं, सरकार की ओर से भाजपा सांसदों ने अपने तरीके से विपक्ष को जवाब दिया। बिप्लव कुमार देब ने कांग्रेस पर तंज कसा- कांग्रेस कह रही है कि भाजपा 400 पार नहीं कर सकी, जबकि खुद कांग्रेस लगातार तीन चुनावों में भी 240 सीटों का आंकड़ा नहीं छू सकी। उन्होंने दावा किया- हम 400 पार करेंगे और 2047 तक एनडीए सरकार भी रहेगी, जो भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

भाजपा सांसद ने संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा

उन्होंने कहा- कांग्रेस की शैलजा कुमारी ने इसे कुर्सी बचाओ बजट नाम दिया है, इसका मतलब है कि उन्हें बिहार और आंध्र प्रदेश की जरूरत नहीं है। उन्होंने संविधान के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। कहा कि जिस कांग्रेस ने सिर्फ एक व्यक्ति इंदिरा गांधी के लिए देश पर आपातकाल थोपा, 70 बार संविधान में संशोधन किए, वह आज संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं।

बजट में दिखता है मोदी सरकार का दूरदर्शी सोच: भर्तृहरि महताब

इसी तरह भर्तृहरि महताब ने कहा कि पहली बार किसी केंद्र सरकार ने विभिन्न प्राकृतिक और मानव संसाधन संपन्न पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के विकास में नीतिगत हस्तक्षेप किया है।

उन्होंने जवाब दिया- विपक्षी दलों ने कहा है कि ओडिशा के लिए बजट में कोई घोषणा नहीं की। उन्हें पूर्वोदय योजना की घोषणा को देखना चाहिए, जिसमें राज्य के चहुंमुखी विकास की बात कही है। यह पांच राज्य विकसित भारत के इंजन साबित होंगे। विपक्ष के आरोप निराधार हैं कि इस बजट पर लोकसभा चुनाव के परिणाम का असर है, बल्कि इसमें मोदी सरकार का दूरदर्शी सोच दिखाई देता है।

बालास्वर जिला प्रशासन ने 10 गांवों के करीब 20 हजार लोगों को अस्थायी तौर पर स्थानांतरित कर दिया

मनोरंजन सासमल स्टेटे हेड उडीशा

भुबनेस्वर, बलेसोर: ओडिशा के बालास्वर जिला प्रशासन ने 10 गांवों के करीब 20 हजार लोगों को अस्थायी तौर पर स्थानांतरित कर दिया है। दरअसल, इन लोगों का तबादला डीआरडीओ द्वारा बुधवार को किए गए मिसाइल परीक्षण के मद्देनजर किया गया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक, मिसाइल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर आईटीए परिसर में किया जाएगा। डीआरडीओ ने मिसाइल परीक्षण के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं. परीक्षण आईटीआर के लॉन्च पैड-3 से किया जाएगा।

दूसरी ओर, बालेश्वर जिला प्रशासन ने 10 गांवों के लगभग 20 हजार लोगों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया है। प्रशासन ने लॉन्च पैड के 3.5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को खाली करा लिया है. अधिकारी ने कहा, इन लोगों को सुरक्षा कारणों से स्थानांतरित किया गया है। इन लोगों को हुई परेशानी को देखते हुए मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है।

अधिकारी ने कहा, जिला प्रशासन ने तैयारियों की निगरानी के लिए मंगलवार को एक बैठक बुलाई। बैठक के बाद लोगों से आज सुबह 4 बजे तक घर छोड़ने को कहा गया। इन लोगों को अगले निर्देश के बाद ही अपने घर लौटने को कहा गया है।

राहुल गांधी ने की किसान नेताओं से मुलाकात, MSP गारंटी के लिए सरकार पर दबाव बनाने का दिया भरोसा

किसान नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान किसान नेताओं ने राहुल से एमएसपी समेत किसानों की अन्य मांगों को संसद में उठाने की मांग बात कही। जिस पर राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि वह आईएनडीआईए के घटक दलों के साथ चर्चा कर संयुक्त रूप से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे।

नईदिल्ली। संसद में छात्रों का मुद्दा उठाने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को किसान नेताओं से चर्चा के दौरान एमएसपी की कानूनी गारंटी की किसानों की मांग को मुखर समर्थन देने का एलान कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के दर्जन भर नेताओं के साथ हुई अपनी बैठक में राहुल गांधी ने एमएसपी की कानूनी गारंटी को किसानों का अधिकार बताते हुए आश्वासन दिया कि आईएनडीआईए गठबंधन इस मामले में किसानों के साथ है।

संसद भवन में नेता विपक्ष के कार्यालय में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक से आए 12 किसान नेताओं की राहुल गांधी के साथ बैठक हुई, जिस दौरान किसानों की तमाम समस्याओं समेत एमएसपी के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद किसान नेताओं संग बाहर आकर राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र में एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा किया गया था। हमने इसका पूरा आकलन किया है और इसका कार्यान्वयन संभव है।

राहुल गांधी ने सरकार पर दबाव डालने का दिया आश्वासन

नेता विपक्ष ने कहा कि इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आईएनडीआईए के सभी घटक दलों के नेताओं से चर्चा कर हम संयुक्त रूप से सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करेंगे, ताकि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलना सुनिश्चित किया जा सके। हरियाणा में किसानों के खिलाफ हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच का मुद्दा भी इन नेताओं ने उठाया और नेता विपक्ष ने संसद में इसे मामले को उठाने का आश्वासन दिया।

ये नेता भी थे बैठक में मौजूद

राहुल गांधी की किसान नेताओं के साथ बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पंजाब के कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी, अमर सिंह के साथ हरियाणा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जय प्रकाश भी मौजूद थे। बैठक में किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में जगजीत सिंह, लखविंदर सिंह, शांता कुमार, अभिमन्यु, एन वेंकटेश्वर राव, पांडियन रामलिंगम, तेजवीर सिंह, स्वर्ण सिंह पंधेर, सुरजीत सिंह, रमनदीप सिंह मान, गुरमनीत सिंह और अमरजीत सिंह शामिल थे।

नेता विपक्ष के कार्यालय में हुई मुलाकात

राहुल गांधी ने किसान नेताओं को संसद भवन में अपने कार्यालय में बैठक के लिए आमंत्रित किया था, मगर शुरुआत में किसानों नेताओं को संसद परिसर में प्रवेश से रोक दिया गया और जब राहुल खुद उनसे जाकर बाहर मिलने के लिए निकले तो फिर किसान नेताओं को नेता विपक्ष के कार्यालय में प्रवेश की अनुमति दी गई।

वेणुगोपाल ने बैठक के बाद एक्स पर पोस्ट में कहा कि सरकार द्वारा ठुकराए जाने, लाठियों से पीटे जाने और गोलियों से स्वागत किए जाने के कारण किसानों ने सरकार से सारी उम्मीदें खो दी हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023